https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

# कमल संदेश

वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ

वर्ष-13, अंक-23 01-15 दिसंबर, 2018 (पाक्षिक) ₹20

## जनता का सतत विकास हेतु भाजपा को समर्थन

विधानसभा चुनावों पर विशेष | विमुद्रीकरण का प्रभाव | सरकार ने जो कहा वह किया

राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) में रोड शो के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह व भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल जैन

रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हेतु अटल संकल्प पत्र-2018 को जारी करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह और अन्य

वैरेंटे (मिजोरम) में आयोजित एक रैली में जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

बैतूल (मध्य प्रदेश) में संपन्न एक विशाल जन सभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

सतना (मध्य प्रदेश) में विशाल रोड शो के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और अन्य

# कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

**संपादक**
प्रभात झा

**कार्यकारी संपादक**
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

**सहायक संपादक**
संजीव कुमार सिन्हा

**संपादक मंडल सदस्य**
सत्यपाल
राम नयन सिंह

**कला संपादक**
विकास सैनी
मुकेश कुमार

**संपर्क**
फोन: +91(11) 23381428

**फैक्स**
फैक्स: +91(11) 23387887

**ई-मेल**
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

**वेबसाइट:** www.kamalsandesh.org


# विषय-सूची

## 06 भाजपा ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 21 नवंबर को मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) के टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित युवा टाउन हॉल कार्यक्रम में राज्य के युवाओं से रू-ब-रू हुए और उनसे...

### वैचारिकी

संस्कृति का अर्थ 15

### श्रद्धांजलि

नहीं रहे केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार 17

### लेख

विमुद्रीकरण का प्रभाव 21

सार्वभौमिक विद्युतीकरण: सरकार ने जो कहा वह किया 23

### अन्य

उत्तराखंड निगम चुनावों में भाजपा की भारी विजय 11

अक्तूबर में खुदरा महंगाई दर 13 महीने के न्यूनतम स्तर (3.31%) पर 13

1.3 अरब भारतीयों के लिये वित्तीय समावेश अब हकीकत बना... 19

कांग्रेस ने झूठ बोलने का रास्ता चुना है और हमने गरीब जनता की सेवा... 25

राज्य में लगातार चौथी बार कमल खिलने वाला है: अमित शाह 27

हमारा मंत्र है- बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई, किसानों... 28

कांग्रेस का न कोई नेता है, न नीति और न नीयत: अमित शाह 30

शिवराजजी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश 'बीमारू' से 'विकसित' बना है 31

'कांग्रेस को एक परिवार के सिवा किसी और की चिंता नहीं है' 32

### स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

## 09 गुजर गई सारी बदहाली, अब है समृद्धि और खुशहाली

2003 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदेश...

## 10 'विकास-गाथा को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने पुन: भाजपा सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ की...

## 12 वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल समेत 2400 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में 12...

## 14 भारत के जीएसएलवी एमके III-डी2 से जीएसएटी-29 का सफल प्रक्षेपण

जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्कIII (जीएसएलवी एमके III-डी2) के दूसरे दौर की...



प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

## twitter

### @narendramodi

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने समाज में भेदभाव खत्म करने की राह दिखाई, लेकिन नामदार और उनके चेले मेरी जाति पूछते रहते हैं। पता नहीं क्यों कांग्रेस जात-पात पर चुनाव लड़ती है। मेरी जाति है - 130 करोड़ भारतीय।

### @AmitShah

'गरीबी हटाओ' का नारा देते-देते गरीबों को ही हटा देने का पाप करने वाली कांग्रेस पार्टी न तो कभी गरीबों का भला कर सकती है और न ही देश का विकास कर सकती है।

### @Ramlal

कार्यकर्ता भाजपा की ताकत है और पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास करती है, इसीलिए हमारा नारा भी है 'बूथ जीता, चुनाव जीता'। मुझे पूरा विश्वास है, हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को जरूर जिताएंगे और हम चौथी बार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।

## facebook

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अब उत्तराखंड के देहरादून जिले के कई क्षेत्रों को भी सस्ती, सुरक्षित और स्वच्छ पाइप्ड गैस मिल सकेगी। सीएनजी के इस्तेमाल से वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा, साथ ही पीएनजी से घरेलू गैस सिलेंडर ढोने से छुटकारा मिलेगा। — **त्रिवेंद्र सिंह रावत**

वर्ष 2018 के इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट सर्वेक्षण के तहत भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन व कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला है। इसके लिए शिक्षा विभाग, शिक्षक वर्ग एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। विद्यार्थी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में उचित सुविधा मिले इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। —**जयराम ठाकुर**

गन्ना विभाग प्रदेश की पहचान रहा है। उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे उर्वर भूमि व पर्याप्त सिंचन व्यवस्था है। उसके बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी उद्योग को हतोत्साहित करने का काम किया। राज्य सरकार गन्ना किसानों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हितों में कई फैसले भी लिए गए हैं। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किया है। परिणामस्वरूप गन्ना किसानों के पिछले कई वर्षों की बकाया धनराशि का बड़ी मात्रा में भुगतान किया गया। — **योगी आदित्यनाथ**

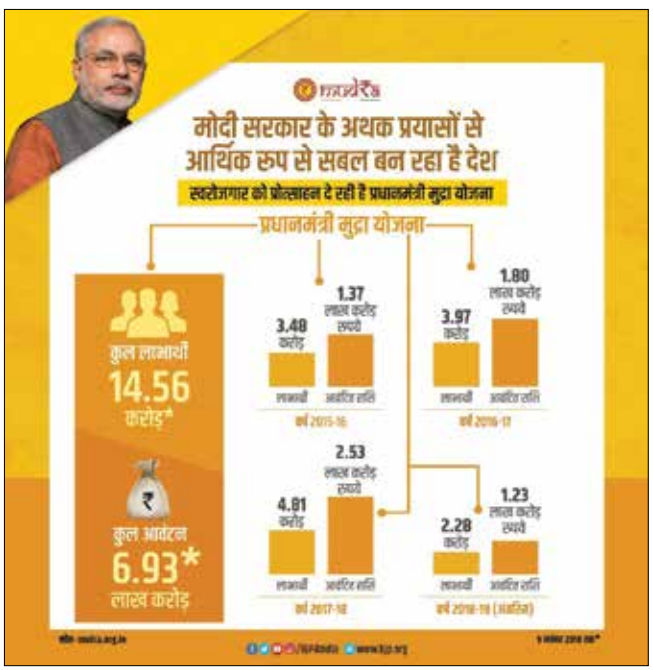


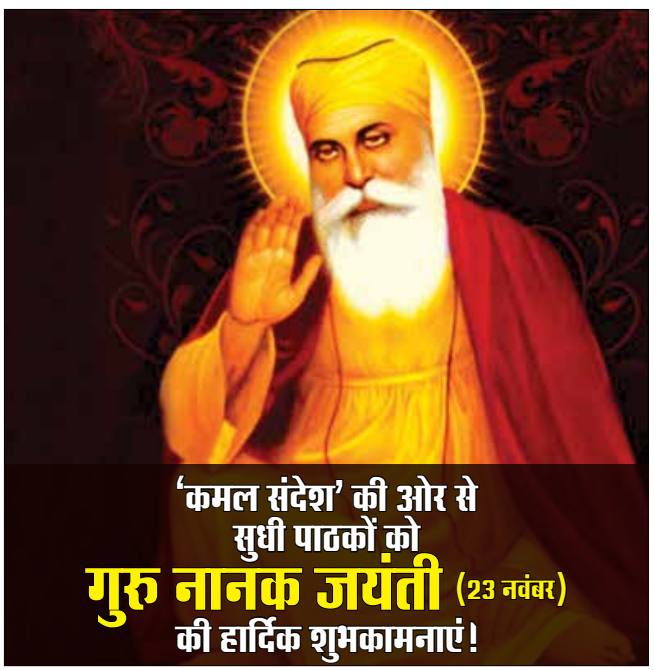

# अब बनी मजबूत भारत की असीम संभावनाएं

भारत अपनी छाप पूरे विश्व पर छोड़ रहा है। सुशासन एवं विकास के लगभग हर मानदंड पर भारत ने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में पूरा विश्व भारत की तरफ आशा एवं आकांक्षा से देख रहा है। वे दिन चले गये जब भारत को नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार एवं कुशासन से ग्रस्त स्व–केंद्रित राजनीतिज्ञों द्वारा शासित एक देश के रूप में देखा जाता था। कांग्रेस नीत यूपीए के शासनकाल में भारत की छवि को गहरा धक्का लगा था और इसके भविष्य के प्रति एक निराशाजनक वातावरण बन गया था। यह छवि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अब पूरी तरह बदल चुकी है। भारत न केवल विश्व में सबसे तेज विकास दर वाला देश बन गया है, बल्कि इसे विश्व अर्थव्यवस्था का एक चमकता सितारा के रूप में देखा जा रहा है। भारत की शक्ति को अब पूरे विश्व में स्वीकार किया जाने लगा है और अधिकतर वैश्विक एजेंसियां एक उभरते हुए मजबूत भारत की संभावनाओं को पहचानने लगी हैं।

पिछले साढ़े चार वर्षों में भारत के उभरने के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में निरंतर चले अथक एवं गंभीर प्रयास हैं। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिये गये अभिनव प्रयासों से देश में व्यापक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। अर्थव्यवस्था, बाहरी या आंतरिक सुरक्षा, आधारभूत संरचनाएं, ग्रामीण एवं शहरी विकास, कृषि आदि किसी भी क्षेत्र पर नजर डालें, परिवर्तन एवं विकास की बयार बहती मिलेगी। देश अकल्पनीय बदलाव की दौर से गुजर रहा है। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार कर, विमुद्रीकरण एवं जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। राजनैतिक–इच्छाशक्ति से परिपूर्ण इन निर्णयों से न केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में गुणात्मक वृद्धि हुई है, बल्कि कर अदायगी में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है जिससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिये पहले से कहीं ज्यादा वित्त उपलब्ध हुआ है। इसका प्रभाव देश के सामाजिक क्षेत्रों में सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप के रूप में दिखाई दे रहा है। देश की अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण भी हुआ है और अब राज्यों के पास वित्त की उपलब्धता बढ़ी है। राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य में व्यापक वृद्धि हुई है।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिये गये अभिनव प्रयासों से देश में व्यापक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। अर्थव्यवस्था, बाहरी या आंतरिक सुरक्षा, आधारभूत संरचनाएं, ग्रामीण एवं शहरी विकास, कृषि आदि किसी भी क्षेत्र पर नजर डालें, परिवर्तन एवं विकास की बयार बहती मिलेगी। देश अकल्पनीय बदलाव की दौर से गुजर रहा है।

देश को चिरप्रतीक्षित भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काले धन, घोटाले और विकास कार्यों में लूट के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। पहले ही कैबिनेट बैठक में कालेधन पर एसआईटी का गठन कर भ्रष्ट, घोटालेबाज एवं हवाला कारोबारियों को सरकार ने कड़ा संदेश दे दिया था। कालेधन के लिए शरणस्थली बनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई कानूनों को बनाकर उन पर लगाम कसी जा चुकी है। इससे बार–बार ठगी और लूटी जा रही आम जनता को भारी राहत मिली है। डीबीटी (सीधा हस्तांतरण) से गरीबों को अब बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है और अब उनका धन सीधे उन्हें अपने खाते में प्राप्त हो रहा है। इन कदमों के साथ–साथ जीएसटी एवं नोटबंदी जैसे बड़े निर्णयों से गरीबी के विरुद्ध लड़ाई तेज हुई है तथा अनेक अभिनव कार्यक्रमों से गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक सुधार हो रहा है।

इन निरंतर चलते अथक प्रयासों का प्रतिफल भारत की मजबूत होती वैश्विक पहचान में परिलक्षित होती है। विश्व बैंक एवं आइएमएफ के साथ–साथ लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मात्र साढ़े चार वर्षों की जबरदस्त उपलब्धियों को स्वीकार रही हैं। अब जबकि भारत फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए विश्व का छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो 2014 की नौंवी स्थान से छठी तक की एक बड़ी छलांग है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मानदंडों में अचंभे में डालने वाली छलांग लगाने वाले भारत के स्वच्छ भारत मिशन की असीम संभावनाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तक भूरि–भूरि प्रशंसा कर रहा है। लगभग हर क्षेत्र में भारत ने अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं तथा अनेक अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम में हर गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला एवं युवा के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। भारत अब उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है जिनके बारे में अभी कुछ वर्ष पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। आने वाले दिन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में एक नई गाथा लिखने को तत्पर है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

# भाजपा ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 21 नवंबर को मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) के टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित युवा टाउन हॉल कार्यक्रम में राज्य के युवाओं से रू-ब-रू हुए और उनसे भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा के साथ जुड़ने का आह्वान किया। श्री शाह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्य के सभी 200 विधानसभाओं के गांवों, कस्बों एवं शहरों से लाइव जुड़े। इस कार्यक्रम में लगभग लाखों युवाओं ने शिरकत की। सोशल मीडिया पर भी युवा टाउन हॉल कार्यक्रम के प्रति देश भर से युवाओं का भारी उत्साह देखा गया। ट्विटर पर हैशटैग #युवां_री_बात_शाह_रे_साथ आज सुबह से देश और दुनिया में टॉप पर ट्रेंड करता रहा। ट्विटर के जरिये देश भर से युवा इस कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन जुड़े, उन्होंने श्री शाह से अपने सवाल भी पूछे। कार्यक्रम को राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष श्री मदनलाल सैनी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में कांग्रेस के 50 वर्ष से अधिक के शासन में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को तबाह कर के रख दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश से इन तीनों बुराइयों को ख़त्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस की अगुआई में फिर से ये बुराइयां सर उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि 2018 का विधानसभा चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ लड़ाई का चुनाव है और यह जंग राजस्थान के युवाओं के बगैर नहीं जीती जा सकती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार युवाओं को एक ऐसा मंच देने का कार्य कर रही है, ताकि वे विश्व के युवाओं से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

भरतपुर संभाग से पुष्पेन्द्र पुष्प के वंशवाद की राजनीति पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि वंशवाद का सबसे खराब उदाहरण हमने अभी राजस्थान में ही देखा है। एक कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन सभा में कांग्रेसी कार्यकर्ता 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं पर दवाब बनाकर

नारा बदलवा दिया और 'भारत माता की जय' की जगह सोनिया गांधी के लिए नारे लगाने को बाध्य किया। राजनीति में वंशवाद का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि इस देश में जिस किसी को भी 'भारत माता की जय' बोलने में हिचकिचाहट होती है, उसे इस धरती का अन्न खाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं कि यदि हम मरणासन्न अवस्था में भी हों और 'भारत माता की जय' का नारा लग रहा हो तो हमारी धड़कनें वापस आ जाती हैं और कांग्रेस पार्टी को भारत माता की जय के नारे लगाने में शर्म आती है! उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में जब तक वंशवाद है, युवाओं का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब घर में पैदा हुए श्री नरेन्द्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्या ऐसा कांग्रेस पार्टी में संभव है?

## राज्य के हर परिवार हुए लाभान्वित

राजस्थान की वसुंधरा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वसुंधरा सरकार की उपलब्धियों की व्याख्या करने के लिए एक ही वाक्य काफी है - "राजस्थान में ऐसा एक भी परिवार नहीं है, जिसे राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार से कोई फायदा न पहुंचा हो। राज्य की भाजपा सरकार ने समाज के हर वर्गों तक, अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है।" उन्होंने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य योजना से 24 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 32 लाख महिलाओं को गैस के कनेक्शन मिले हैं, मुद्रा योजना से राज्य के लगभग 40 लाख लोगों को स्वरोजगार मिला है। लगभग 13 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है, लगभग 50 लाख लोगों को मोबाइल मिला है। लगभग 11 लाख बालिकाओं को राजश्री योजना का फायदा मिला है, 80 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है, बेटियों को लैपटॉप और स्कूटी मिली है और राज्य के 40 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा से लाभान्वित हुए हैं। लाखों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में राजस्थान की भाजपा सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में ई-मित्र में 900%, आईटीआई में 95%, मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 100%, स्नातक सीटों में 100%, राजकीय कॉलेजों की संख्या में 47%, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 150% एवं राजकीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले में 20% की वृद्धि हुई है।

श्री शाह ने कहा कि पांच वर्ष पूर्व कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय राजस्थान का बजट महज 94,000 करोड़ रुपये था, जबकि वसुंधरा सरकार के समय यह बढ़कर 2,12,000 करोड़ रुपये तक पहुंची है जो अपने-आप में राज्य की विकास-गाथा को बयां करने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार केवल 52,000 करोड़ रुपये का ही राजस्व अर्जित कर पाती थी जबकि वसुंधरा सरकार के प्रयासों के कारण यह अब बढ़कर 103000 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। प्रति व्यक्ति आय पांच वर्ष में ही 61,000 रुपये से बढ़कर 76,000 करोड़ रुपये हो गई है। वसुंधरा सरकार ने केवल पांच वर्षों में ही भू-जल स्तर को 11 फुट ऊपर लाने का सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

## राजस्थान के विकास के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए मोदी सरकार ने काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट को हमसे कामकाज का हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि देश की जनता उनसे कांग्रेस पार्टी की चार पीढ़ियों के कामकाज का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग के दौरान कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन-राहुल सरकार ने राजस्थान को केवल 1,09,244 करोड़ रुपये दिए, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में 2,63,580 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाओं में राजस्थान को केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से लगभग 36,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तीन खानों की नीलामी से राजस्थान को 17,000 करोड़, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से लगभग 2000 करोड़ और उज्जवल डिस्कॉम से लगभग 21,000 करोड़ रुपये राजस्थान को मिले। इस तरह राजस्थान को लगभग 88,000 करोड़ रुपये अलग से प्राप्त हुए।

उन्होंने कहा कि देश में 55 साल तक गांधी-नेहरू परिवार का पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक शासन रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने देश के 50 करोड़ गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने स्थिति में परिवर्तन लाने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पिछले साढ़े चार वर्षों में लगभग साढ़े पांच करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। लगभग 8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, बिजली से वंचित 18

**हम तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं कि यदि हम मरणासन्न अवस्था में भी हों और 'भारत माता की जय' का नारा लग रहा हो तो हमारी धड़कनें वापस आ जाती हैं और कांग्रेस पार्टी को भारत माता की जय के नारे लगाने में शर्म आती है! देश की राजनीति में जब तक वंशवाद है, युवाओं का भला नहीं हो सकता।**

हजार से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाई गई। सौभाग्य योजना के तहत दो करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, 13 करोड़ से अधिक बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया और दो करोड़ लोगों को घर उपलब्ध कराये गए।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के नए पैरामीटर स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अर्थव्यवस्था के ताजे आंकड़े से यह सामने आया है कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की विकास दर 8.2% तक पहुंच गई है, जबकि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में यह 4% के आस-पास थी। यूपीए सरकार के समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 9वें स्थान पर था, जबकि आज भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम तेज गति से विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और ऐसी स्थिति पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार के कार्यों से बनी है। ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार के समय भारत ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142वें स्थान पर था जबकि मोदी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में हम कई पायदान ऊपर उठ कर 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं। महंगाई दर भी 8.4% से घट कर 3.3% पर आ गई है और अपने 10 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने जितने हाइवे और रेलवे लाइन बनाये, उससे कहीं अधिक मोदी सरकार ने केवल साढ़े चार साल में बना कर दिखा दिया है।

## कांग्रेस की नफरत की घातक राजनीति

राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी जी, आप प्यार की बातें न ही करें तो अच्छा है। याद कीजिये कि आपकी कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री पीवी नरसिम्हाराव जी और श्री सीताराम केसरी जी से किस तरह का दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि श्री नरसिम्हाराव जी के पार्थिव शरीर तक को कांग्रेस के मुख्यालय में घुसने नहीं दिया गया था और उनका अंतिम संस्कार भी हैदराबाद में हुआ। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में जिस तरह से पार्टी और देश ने एकजुट होकर उन्हें सम्मान दिया, यह हमारे संस्कार दर्शाते हैं। राहुल जी, आपके मुंह से प्यार की परिभाषा अच्छी नहीं लगती।

## अवैध घुसपैठिये कांग्रेस के लिए वोटबैंक

एनआरसी पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को कठघरे में खड़ा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिये देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें अपना वोटबैंक नजर आता है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान आये दिन घुसपैठिये देश की सुरक्षा में सेंध लगाते रहते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केवल वोट बैंक की चिंता रहती थी। जब हमने देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए NRC का काम शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने हायतौबा मचा दी, उसे अवैध घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता सताने लगी। क्या देश की जनता का, असम के नागरिकों का कोई मानवाधिकार नहीं है? उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप राज्य में वसुंधरा सरकार और केंद्र में मोदी सरकार फिर से बना दीजिये, एक-एक घुसपैठियों की पहचान की जायेगी और उन्हें नागरिकता सूची से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट की चिंता है, जबकि देश की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निर्णायक राष्ट्र बना है और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये देश ने यह दिखा दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वह कोई भी कठोर कदम उठा सकती है।

## जीत का दिवास्वप्न देख रही कांग्रेस, हकीकत से है कोसों दूर

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में अपनी जीत का दिवास्वप्न दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले साढ़े चार सालों में कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई है कि उसे दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनाव और उसके बाद देश में संपन्न हुए लगभग सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की पराजय निश्चित है।

## चौकीदार चौकन्ना, चोर कभी चोरी नहीं कर सकते

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को बरगलाने के लिए अब नया खेल शुरू किया है - झूठ बोलना, बार-बार झूठ बोलना, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना और उस झूठ को सच बनाने के लिए प्रयास करना। एक छोटी सी बच्ची रचना की कहानी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि बालिका रचना ने मुझे एक कहानी सुनाई कि 40 चोर एक कॉलोनी में चोरी करना चाहते थे लेकिन मुस्तैद चौकीदार इतना चौकन्ना था कि 40 चोर एक बार भी कॉलोनी में चोरी नहीं कर पाए। तब चोरों ने गठबंधन बना लिया और कॉलोनी वालों के सामने चौकीदार को ही चोर साबित करने में लग गए लेकिन कॉलोनी की जनता समझदार थी। उन्होंने चोरों की साजिश को पहचान लिया और उन्हें जेल भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गठबंधन के सहारे अपनी नैया को पार लगाने का सपना संजो रहे हैं, लेकिन गठबंधन एक ढकोसला मात्र है। गठबंधन बनने के बावजूद हम 2019 में पिछली बार से भी अधिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनायेंगे। ■

# गुजर गई सारी बदहाली, अब है समृद्धि और खुशहाली

2003 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदेश की बदहाली थी। सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं का निदान खोजना ही सरकार की प्राथमिकता थी, लेकिन पिछले 15 सालों में प्रदेश ने विकास के रास्ते पर लंबा सफर तय किया है। बदहाली काफी पीछे छूट गई है और अब सरकार की दृष्टि प्रदेश को समृद्ध बनाने पर है। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिपत्र प्रदेश की समृद्धि की राह दिखाता है। यह बात 17 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव दृष्टिपत्र को जारी करते हुए कही। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए अपना दृष्टिपत्र प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में जारी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्रसिंह तोमर, श्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, उपाध्यक्ष एवं सांसद श्री प्रभात झा, प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह, वरिष्ठ नेता श्री विक्रम वर्मा एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय उपस्थित थे। मंच का संचालन प्रदेश महामंत्री व सांसद श्री अजयप्रताप सिंह ने किया।

दृष्टिपत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री जेटली ने कहा कि हमारा दृष्टिपत्र बताता है कि कांग्रेस सरकार के समय बीमारू राज्य रहा मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में कहां पहुंच गया है और अब उसकी प्राथमिकताओं में क्या बदलाव आया है। श्री जेटली ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने विरासत में जो बदहाली प्रदेश को दी थी, उससे बाहर निकल कर मध्यप्रदेश ने अब 10 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली है, जो देश की विकास दर से ज्यादा है। इसमें प्रदेश की कृषि विकास दर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो 20 प्रतिशत के आसपास रही है और 2003 में कोई इतनी तेज विकास दर की कल्पना भी नहीं कर सकता था। श्री जेटली ने कहा कि कांग्रेस सरकार का बजट 21000 करोड़ रुपये का था, शिवराज जी की सरकार ने इसे 10 गुना बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाकर प्रदेश की भाजपा सरकार ने शासन और राजनीति के एजेंडा को बदला है और लोगों में नई उम्मीद जगाई है।

श्री जेटली ने कहा कि मध्यप्रदेश की तरह देश ने भी पिछले 4 सालों में तेजी से विकास किया है। यूपीए सरकार के समय अर्थव्यवस्था के मामले में देश 142 वें स्थान पर था, जो अब 65 वें स्थान पर आ गया है और अब इसे 50 वें स्थान तक पहुंचाना भी मुश्किल नहीं लगता। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय जिस देश के नाम के साथ 'पॉलिसी पैरालिसिस' और 'फ्रेजाइल फाइव' जैसे विशेषण लगे थे, वहीं देश अब दुनिया की पांच सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। देश में इनफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हुआ है। अब देश में हर साल 10 हजार कि.मी. हाइवे और 140 एयरपोर्ट तैयार हो जाते हैं। श्री जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था में हुए इस सुधार की बदौलत ही सरकार हर साल गरीबों को खाद्यान्न सब्सिडी दे पा रही है, मनरेगा का बजट दोगुना किया है, 7 लाख गांवों में ग्रामीण सड़कें और गांवों के 92 प्रतिशत घरों में शौचालय बनाए हैं। पहले 5 करोड़ घरों में उज्जवला योजना के गैस कनेक्शन दिए गए, जिन्हें अब 8 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसाधनों पर समाज के हर वर्ग का हक है और हमारा दृष्टिपत्र हर गरीब को उसकी बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की पढ़ाई और बीमारों की दवाई उपलब्ध कराने का संकल्प पत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के दृष्टिपत्र में गरीबों और किसानों को प्राथमिकता दी गई है।

दृष्टिपत्र तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए दृष्टिपत्र समिति के संयोजक वरिष्ठ नेता श्री विक्रम वर्मा ने कहा कि इसलिए हमारे दृष्टिपत्र में शामिल बातें कोरी कल्पना नहीं हैं, बल्कि उन बातों को यथार्थ में लागू करने की योजना है। समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह ने कहा कि दृष्टिपत्र में प्रदेश के सुखद कल की झलक है। ■

# 'विकास-गाथा को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने पुनः भाजपा सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश के विकास का अगले पांच वर्ष के लिए "अटल संकल्प पत्र" जारी किया और छत्तीसगढ़ को नक्सल-मुक्त राज्य बनाने का संकल्प व्यक्त करते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का "नवा छत्तीसगढ़" बनाने का खाका राज्य की जनता के सामने रखा। इसके पश्चात श्री शाह ने गांधी मैदान, राजिम (गरियाबंद) में एक विशाल जन-सभा को संबोधित किया। तत्पश्चात् उन्होंने राजनंदगांव में गंज चौक से मानव मंदिर तक एक भव्य रोड शो किया। रोड शो के समापन पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री रमन सिंह जी के प्रति अपार जनसमर्थन से यह निश्चित है कि यहां की जनता पिछले बार से भी अधिक बहुमत के साथ उन्हें विजयी बनाएगी और उन्हें पुनः राज्य के विकास की बागडोर सौंपेगी।

श्री शाह ने अटल संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह द्वारा पिछले 15 वर्षों में किये गए जनकल्याण कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि इस समय छत्तीसगढ़ में मणिकंचन का योग है। केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की और छत्तीसगढ़ में भी रमण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। इन दोनों के प्रयासों से यह राज्य सफलता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह मणिकंचन योग आगे भी बना रहेगा।

अटल संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ के लिए "अटल संकल्प पत्र" भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की लोक-कल्याणकारी सरकार के संकल्प, कार्यसंस्कृति एवं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र राज्य के विकास को एक नई उड़ान देगा और छत्तीसगढ़ की आम जनता के जीवन-स्तर को और ऊंचा उठाने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश का कभी हिस्सा रहा छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य की श्रेणी में था, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कुशल नेतृत्व में यह अब पिछड़ा नहीं बल्कि पॉवर हब बन चुका है और विगत 15 सालों से शिक्षा और स्वास्थ्य का हब बना, छत्तीसगढ़ राज्य जल्द ही डिजिटल हब भी बनेगा।

श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार फिर से राज्य में विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए श्री रमण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है। ■

**छत्तीसगढ़ में पुनः भाजपा सरकार गठित होने पर 12वीं तक सभी छात्र-छात्राओं को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। कक्षा नौ तक के छात्रों को मुफ्त साइकिल मिलेगी। आदिवासी बच्चों के कल्याण के लिए राज्य में 184 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। राज्य में फिर से रमन सिंह सरकार बनने पर पत्रकारों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने पर राज्य में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। राज्य को विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भाजपा सरकार हर व्यक्ति को आवास की कल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास दिया जायेगा। स्वास्थ्य बीमा को और बेहतर बनाया जाएगा, जिसके तहत आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा और अभी यूनिवर्सल हेल्थ बीमा की रकम को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा। राज्य में फिर से भाजपा सरकार बनने पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के भूमिहीन मजदूरों और छोटे कृषकों को 1 हजार रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। राज्य में सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए स्टॉप डेम के विकास पर बल दिया जाएगा।**

# उत्तराखंड निगम चुनावों में भाजपा की भारी विजय

भाजपा ने उत्तराखंड निगम चुनावों में सात मेयर सीटों में से पांच तथा 34 चेयरमैन एवं अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने 23 सीटों पर जीत हासिल की।

कांग्रेस ने राज्य निगम चुनावों में चेयरमैन और अध्यक्ष पद की 25 सीटों पर जीत हासिल की। 21 नवंबर को देहरादून में राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार बसपा को एक सीट पर विजय मिली। एक पद के परिणाम अभी भी आने बाकी हैं।

आयोग ने बताया कि भाजपा ने सात मेयर की सीटों में से पांच पर विजय प्राप्त की जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, रूद्रपुर और हलद्वानी शामिल है, जबकि कांग्रेस ने हरिद्वार और कोटद्वार सीटें जीतीं।

**@narendramodi**

मैं राज्य के लोगों द्वारा लगातार समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, जिसमें स्थानीय नगर निकाय चुनावों में हमारी पार्टी को समर्थन मिला है। मैं स्थानीय ईकाई को उनके कठिन परिश्रम और प्रयास के लिए बधाई देता हूं, जिससे यह जीत संभव हो सकी।

18 नवंबर को उत्तराखंड में 84 स्थानीय नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए जिसमें 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सहित 39 म्युनिसिपिल परिषद और 38 नगर पंचायतें शामिल थीं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव परिणाम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था जताई है।

श्री रावत ने चुनाव परिणामों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा को फिर से समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समग्र रूप से परिणाम से संकेत मिलता है कि लोगों ने एक बार फिर भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त की है। ■

**मिजोरम**

# 'कांग्रेस को बाहर करो और भाजपा सरकार लाओ'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पंथनिरपेक्ष तथा शांतिपूर्ण मिजोरम बनाने का वायदा किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग प्रगति कर सकेंगे।

श्री शाह ने 20 नवंबर को वैरेंटे एवं लॉन्गतलाई (मिजोरम) में आयोजित चुनावी रैलियों को सम्बोधित करते हुए उक्त बातें कहीं।

श्री शाह ने कहा कि संविधान की छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश के लोग प्रगतिशील भाजपा सरकार ला सकते हैं तो क्यों मिजोरम भी भाजपा परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती? भाजपा सरकार ने बंद और रुकावट डालने का युग समाप्त कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि मिजोरम में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं, परंतु सड़क कनेक्टिविटी के अभाव ने इसे स्थिर बना दिया है। कांग्रेस बहुत लम्बे समय से मिजोरम के लोगों की भावनाओं के साथ खेल खेल रही है। उन्हें अधिकारों की शिक्षा के बजाए ''पैसे के लिए वोटों'' की शिक्षा दी गई है। कांग्रेस को बाहर निकालो और सभी के लिए भाजपा सरकार लाओ।

कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मिजोरम में

''पैसे के लिए वोट'' संस्कृति लाई है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस और एमएनएफ शासन के अधीन ट्यूरियल हाइडल प्रोजेक्ट के निर्माण में 18 वर्ष लग गए। ■

# वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल समेत 2400 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में 12 नवंबर को गंगा नदी पर मल्टीमॉडल टर्मिनल समेत 2400 करोड़ रुपये लागत वाली विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। यही नहीं, श्री मोदी ने वाराणसी शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला भी रखी।

प्रधानमंत्री ने वाराणसी रिंग रोड फेज-1 और राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के विकास और इसके बाबतपुर-वाराणसी खंड को चार लेन का बनाने के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। 34 किलोमीटर लंबे इन मार्गों के निर्माण में 1571.95 करोड़ रुपये की लागत आई है। 16.55 किलोमीटर लंबे वाराणसी रिंगरोड़ फेज़-1 का निर्माण कार्य 759.36 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है। बाबतपुर-वाराणसी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 पर 17.25 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 812.59 करोड़ रुपये की लागत आई है। बाबतपुर हवाई अड्डा राजमार्ग वाराणसी को हवाई अड्डे के साथ ही जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ से भी जोड़ता है।

इस अवसर पर विशाल जन-समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन काशी, पूर्वांचल, पूर्वी भारत और समूचे देश के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि आज जो विकास कार्य हुए हैं, वे दशकों पहले पूरे हो जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि वाराणसी के साथ पूरा देश आज ये देख रहा है की अगली पीढ़ी के ढांचे का विजन किस तरह देश के यातायात साधनों का कायाकल्प कर रहा है।

वाराणसी में प्रथम अंतर-देशीय कन्टेनर पोत पहुंचने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अब जल मार्ग से बंगाल की खाड़ी से जुड़ गया हैं। उन्होंने कई अन्य परियोजनाओं की भी चर्चा की जिनमें सड़कों और नमामि गंगे से सम्बद्ध परियोजनाएं शामिल थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्देशीय जल मार्ग से समय और धन की बचत होगी, सड़कों पर जाम लगने से निजात मिलेगी, ईंधन की लागत में कमी आयेगी और वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में आधुनिक ढांचे का तेजी से निर्माण हुआ है।

उन्होंने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में हवाई अड्डों का निर्माण, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में सड़कों का सुदृढ़ नेटवर्क कायम किया है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां सरकार की पहचान बन गई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे के अंतर्गत अभी तक 23000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारे स्थित सभी गांव खुले में शौच जाने से मुक्त हो गये हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता का हिस्सा हैं।

## गंगा के अविरल प्रवाह के लिए नदी में पर्याप्त जल सुनिश्चित किया जायेगा: नितिन गडकरी

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, सड़क परिहन और राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उपरोक्त अवसर पर कहा कि गंगा नदी में पर्याप्त जल सुनिश्चित करने के भी उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए नदी के प्रारंभिक स्थान गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल में अंतिम बिन्दु गंगा सागर तक विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ के दौरान वाराणसी और प्रयागराज के बीच नौकाएं चलेंगी।

श्री गडकरी ने कहा देश में हज़ारों करोड़ रुपये की लागत से 268 जल स्वच्छता परियोजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में गंगा में 80 स्थानों पर की गई जल गुणवत्ता जांच के दौरान 55 स्थानों पर जल स्वच्छ पाया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर कि इन उपायों के अच्छे परिणाम सामने आयेंगे और आगामी मार्च तक 70 से 80 प्रतिशत गंगा स्वच्छ हो जायेंगी। ■

# अक्तूबर में खुदरा महंगाई दर 13 महीने के न्यूनतम स्तर (3.31%) पर

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) 3.31% रही, जो 13 महीने का न्यूनतम स्तर है। अक्टूबर महीने में फल, प्रोटीन वाले उत्पाद तथा खाने पीने की वस्तुओं के दाम घटने से खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 3.31 प्रतिशत पर आ गई। यह खुदरा मुद्रास्फीति का सितंबर, 2017 के बाद का निचला स्तर है। उस समय यह 3.28 प्रतिशत थी। इससे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर, 2018 में 3.7 प्रतिशत पर और अक्टूबर, 2017 में 3.58 प्रतिशत पर थी।

इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 2.82 फीसदी (अनंतिम) रही, जो अक्टूबर, 2017 में 3.36 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2018 में 3.97 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई, जो अक्टूबर, 2017 में 3.81 फीसदी थी। ये दरें सितम्बर, 2018 में क्रमशः 3.27 और 4.31 फीसदी (अंतिम) थीं।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 12 नवंबर को अक्टूबर, 2018 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़ें भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर (-)0.57 फीसदी (अनंतिम) रही, जो अक्टूबर, 2017 में 1.75 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2018 में (-)1.15 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई, जो अक्टूबर, 2017 में 2.13 फीसदी थी। ये दरें सितम्बर, 2018 में क्रमशः 0.87 और (-)0.22 फीसदी (अंतिम) थीं।

अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2018 में 3.31 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई है, जो अक्टूबर, 2017 में 3.36 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2018 में 3.70 फीसदी (अंतिम) थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2018 में (-) 0.86 फीसदी (अनंतिम) रही, जो अक्टूबर, 2017 में 1.90 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर सितम्बर, 2018 में 0.51 फीसदी (अंतिम) थी। ■

## नवरत्न 'नेशनल अल्युमिनियम कंपनी' (नाल्को) का प्रथम छमाही में शुद्ध लाभ तीन गुना बढ़ा

# नाल्को का शुद्ध मुनाफा 1197 करोड़ रुपये

खान मंत्रालय के अधीनस्थ एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) नेशनल अल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) ने एक बार फिर वित्तीय मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन किया। 13 नवंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही में कंपनी ने 5,952 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जो वित्त वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में किए गए कारोबार (टर्नओवर) की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है।

नाल्को का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही में 229 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्शाते हुए 1197 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष (2017-18) की प्रथम छमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 364 करोड़ रुपये आंका गया था।

चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में जहां एक ओर नाल्को का शुद्ध मुनाफा लगभग तीन गुना बढ़ गया, वहीं दूसरी ओर कंपनी का परिचालन मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में अर्जित 334 करोड़ रुपये की तुलना में इस दौरान चार गुना से भी अधिक बढ़कर 1624 करोड़ रुपये के स्तर को छू गया है। कंपनी का ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और कर्ज अदायगी पूर्व कमाई) मार्जिन 17 प्रतिशत से दोगुना होकर 34 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। ■

# वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवंबर को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुंडली-मानेसर खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने बल्लभगढ़-मुजेसर मेट्रो लिंक का भी उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे और मेट्रो कनेक्टिविटी से हरियाणा में परिवहन के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात होगा। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से इस क्षेत्र के युवा बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि केएमपी एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे 'जीविका में आसानी (ईज ऑफ लिविंग)' सुनिश्चित होगी और इसके साथ ही पर्यावरण अनुकूल माहौल में आवाजाही करना संभव होगा।

प्रधानमंत्री ने परिवहन के जरिए कनेक्टिविटी की अहमियत पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह समृद्धि, सशक्तिकरण और सुगम्यता का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बनाए जा रहे विभिन्न राजमार्गों, मेट्रो और जलमार्गों से विशेषकर विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार अवसर सृजित होंगे। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि वर्तमान में प्रतिदिन 27 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2014 में राजमार्ग निर्माण का यह दैनिक आंकड़ा 12 किलोमीटर ही था। उन्होंने कहा कि यह भारत में व्यापक बदलाव लाने संबंधी केन्द्र सरकार के विजन एवं दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के युवाओं की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं का कौशल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिससे कि वे नए अवसरों से लाभ उठा सकें।

प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार के विजन को सफलतापूर्वक साकार करने के लिए हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने देश, विशेषकर खेल-कूद के क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के उल्लेखनीय योगदान की भी सराहना की। ■

# भारत के जीएसएलवी एमके III-डी2 से जीएसएटी-29 का सफल प्रक्षेपण

जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्कIII (जीएसएलवी एमके III-डी2) के दूसरे दौर की उड़ान से 14 नवंबर को सतीश भवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी) श्रीहरिकोटा से जीएसएटी-29 संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

जीएसएलवी एमके III-डी2 को 3423 किलोग्राम वाले जीएसएटी-29 उपग्रह के साथ सतीश भवन अंतरिक्ष केन्द्र के दूसरे प्रक्षेपण पैड से प्रक्षेपित किया गया। लगभग 17 मिनट के बाद इस प्रक्षेपण यान द्वारा योजना के अनुसार उपग्रह को जियोसिंक्रोनस स्थापन कक्ष (जीटीओ) में स्थापित कर दिया।

स्थापित करने के बाद हासन स्थित इसरो की शीर्ष नियंत्रण इकाई ने उपग्रह के नियंत्रण का जिम्मा ले लिया है। आने वाले दिनों में उपग्रह को भूस्थैतिक कक्ष में इसके निर्धारित स्थान पर तीन कक्षों में स्थापित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस तीन स्तरीय भारी प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एमके III को तैयार किया है।

इसके सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने कहा, 'अपनी धरती से अपने सबसे भारी प्रक्षेपक की मदद से सबसे भारी उपग्रह को प्रक्षेपित करके भारत ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तय किया है। प्रक्षेपण यान की मदद से अपने लक्षित कक्ष में उपग्रह को पूर्णतः स्थापित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए मैं इसरो की पूरी टीम को बधाई देता हूं।' ■

### प्रधानमंत्री ने जीएसएटी-29 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसएलवी एमके III-डी2 के द्वारा जीएसएटी-29 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि जीएसएटी-29 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर अपने वैज्ञानिकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। किसी भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा कक्ष में सबसे भारी उपग्रह स्थापित किये जाने की दोहरी सफलता से एक नया कीर्तिमान कायम हुआ है। इस उपग्रह से हमारे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में संचार और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होंगी।

# संस्कृति का अर्थ

दीनदयाल उपाध्याय

आम लोगों ने यहां संघ कार्य के अनेक रूपों का विचार किया होगा। एक प्रश्न हमारे सामने यह भी आता है कि समय-समय पर हम कहते हैं कि हमारा कार्य सांस्कृतिक अधिष्ठान पर खड़ा है। इस दृष्टि से यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि वह संस्कृति क्या है? संघ की प्रतिज्ञा में भी हम ऐसा कहते हैं, 'हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की रक्षा कर हिंदू समाज की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए हम संघ के घटक बने हैं।' बिना संस्कृति संरक्षण के राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती, यह भी हम स्वीकारते हैं।

आख़िर संस्कृति है क्या? हम यह भी देखते हैं कि संस्कृति के नाम पर आज देश में बहुत से कार्य प्रारंभ हो गए हैं। हर कहीं हम Cultural progress का नाम सुनते हैं। हमारे कलाकार सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के रूप में विदेश जाते हैं, अन्य देशों से हम संस्कृति का संबंध जोड़ते हैं आदि। कहने का तात्पर्य यह कि हम नाच-गान को ही संस्कृति मान बैठते हैं।

भारत के विचारकों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गाना, नाचना, नाटक खेलना मात्र ही संस्कृति है। यदि यही संस्कृति की परिभाषा है तो इसका प्रचार हमारे पूर्वज ऋषियों, विद्वानों, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों द्वारा न होकर फ़िल्म अभिनेता तथा अभिनेत्रियों द्वारा ही होगा।

संस्कृति शब्द को आज ग़लत अर्थ ही दिया गया है। यह अज्ञानवश हो सकता है और जानबूझकर भी। जानबूझकर इसलिए कि अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए वे संस्कृति शब्द का उपयोग उन लोगों में ग़लत धारणा पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जैसे डालडा को घी की संज्ञा देने से यह बात स्पष्ट है। घी शब्द के बारे में लोगों की धारणा अच्छी है। इसलिए डालडा के साथ साफ़ किया हुआ तेल-ऐसा न जोड़कर घी शब्द जोड़ दिया गया है। कुछ समय उपरांत लोग इस डालडा को ही वास्तविक घी समझकर इसका उपयोग करने में लज्जा महसूस नहीं करेंगे। ठीक यही बात संस्कृति के संबंध में है। संस्कृति के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उन्हें ग़लत रास्ते पर डालने के लिए इस नवीन संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। राष्ट्रीयता के संबंध में भी यही बात हुई । हमें Indian Nationalism की भ्रांत धारणा दी गई और कहा गया कि मुसलमान, ईसाई सभी यहां के राष्ट्रीय हैं। सिक्खों को यह ग़लत धारणा दी गई कि वे हिंदू नहीं हैं आदि।

आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में इसी कारण लोगों की कल्पना नाचने-गाने की ही हो गई है। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहते हैं कि हमारा कार्य सांस्कृतिक है, परंतु हमें तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां तो नाच-गाना होता नहीं। फिर मैंने व्यंग्य कसते हुए कहा कि जिस प्रकार नाचने-गाने में वे स्वर-ताल का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार संघ के कार्यक्रमों में एक कहने पर बायां पैर और दो कहने पर दायां पैर निकलता है और एक ताल के अनुसार कार्य होता है, इसलिए यह भी सांस्कृतिक हुआ।

संस्कृति के पीछे क्या भाव है, यह समझना कुछ कठिन है। संस्कृति शब्द का प्रयोग वेदों को छोड़कर अन्य प्राचीन वाङ्मय में नहीं हुआ। संस्कृति को धर्म के अंतर्गत ही मान लिया गया था, परंतु आज संस्कृति शब्द का व्यापक प्रचार होने के कारण लोग इस शब्द को सुनकर चौंकते नहीं। कुछ लोगों ने इसे Culture के अनुवाद के रूप में स्वीकार किया है। यह भी संभावना हो सकती है कि यह शब्द स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ हो। संस्कृति से मिलता-जुलता संस्कार शब्द हमारा पूर्व परिचित शब्द है। हमारे यहां सोलह संस्कार होते हैं, संस्कारों से मनुष्य बनता है, बिना संस्कार के वह पशु समान है- ऐसा बराबर सुनने में आता है। साधारणतया हम कह सकते हैं कि जो बाह्य वातावरण है, उसका मनुष्य पर जो परिणाम होता है, उसे हम संस्कार (Impression) कह सकते हैं।

परंतु संस्कार अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। किसी को चोरी की आदत लग जाए तो हम कहेंगे, उस पर बुरे संस्कार पड़े हैं। परंतु जब हम संस्कार कहते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय अच्छे संस्कार से ही होता है। बुरे संस्कारों के लिए हम कुसंस्कार शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे चरित्रवान् कहने से हमारा आशय अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति से होता है, जबकि बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के लिए हम चरित्रहीन शब्द का प्रयोग करते हैं।

अतः संस्कृति का अर्थ हुआ, अच्छे संस्कारों का परिणाम (प्रभाव)। मलयालम भाषा में हिंदू संस्कृति के लिए हिंदू संस्कार शब्द का प्रयोग होता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किन संस्कारों को हम अच्छा कहेंगे और किनको बुरा। इसकी व्याख्या करना सरल नहीं। पर एक छोटी सी कसौटी तो है। वह यह कि समाज के ध्येय के लिए जो पोषक है, वह अच्छा और जो बाधक है, वह बुरा। जैसे यदि हमारा लक्ष्य दिल्ली जाना है, तो जो रेलगाड़ी या मोटरगाड़ी उधर ले जाने में सहायक हो, वह अच्छी और जो विपरीत दिशा में ले जानेवाली है, वह बुरी।

परंतु दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ध्येय क्या है? इस संबंध में हम इतना जानते हैं कि हमारी जो एकात्मकता है, एकीकरण है, इसकी अनुभूति ही हमारा ध्येय है। जब सब लोग एकता का अनुभव करें, तभी समाज अथवा राष्ट्र बनता है। यदि हम राष्ट्र के नाते जीवित रहना चाहते हैं तो एकात्मकता की अनुभूति जिससे होगी, वही हमारा ध्येय होगा।

यदि पांव में कांटा चुभ जाए और पता न लगे कि कहां चुभा है तो चिंता होने लगती है। शरीर के कण-कण की जब तक ठीक अनुभूति रहती है, तब तक ठीक है, परंतु जब बेहोशी आदि में शरीर का ज्ञान नहीं रहता, क्रियाओं, चेष्टाओं का ज्ञान नहीं रहता तो वह स्थिति चिंताजनक होती है और सारा शरीर गया, ऐसा लगने लगता है। जैसे लकवे में हाथ होते हुए भी हाथ की क्रिया रुक जाती है, हाथ की अनुभूति नहीं होती। जब तक शरीर में चेतना है, अंगों का संबंध बराबर बना रहता है। तभी तक हममें सामर्थ्य है, जीवन है। इसी प्रकार राष्ट्र रूपी शरीर में चेतना बनाए रखना आवश्यक है। अतः जिन कारणों से राष्ट्र में चेतना का निर्माण होता है, वे अच्छे और दूसरे बुरे।

प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना जिससे बनी रहे, वही संस्कृति का आधार माना जाता है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। आत्मा निकल जाने के पश्चात् जैसे सब अंग-प्रत्यंग निश्चेष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार की अवस्था संस्कृति का लोप हो जाने से राष्ट्र की होती है। जैसे यूनान और मिस्र का प्राचीन राज्य समाप्त हो गया। इसका यह अर्थ तो नहीं कि वहां की भूमि, नदियां, पर्वत, व्यक्ति आदि नष्ट हो गए। ये वस्तुएं तो ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं, परंतु व्यक्ति को एकसूत्र में बांधने की जो शक्ति संस्कृति में है, वह शक्ति समाप्त हो जाती है। लकड़ियों को सूत के धागे से बांधा जा सकता है परंतु व्यक्ति-व्यक्ति को बांधने वाला सूत्र संस्कृति ही है। यह सूत्र वर्तमान प्राणियों के अतिरिक्त हमारा संबंध हमारे पूर्वजों अर्थात् राम, कृष्ण, शिवा, प्रताप, गोविंद सिंह आदि से तथा आगे जन्म लेनेवालों से भी जोड़ देता है। इसी के बूते पर राष्ट्र टिक सकता है। अतः राष्ट्र रूप में जीवित रहने के लिए यही संस्कृति प्राप्तव्य है। अतः सिद्ध हुआ कि सारे समाज को आपस में जोड़ने वाला नाता संस्कृति है। जिन कार्यक्रमों से यह नाता जुड़ता है, वह संस्कार तथा जिन कार्यों से यह नाता टूटने लगता है, वे कुसंस्कार।

**प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना जिससे बनी रहे, वही संस्कृति का आधार माना जाता है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। आत्मा निकल जाने के पश्चात् जैसे सब अंग-प्रत्यंग निश्चेष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार की अवस्था संस्कृति का लोप हो जाने से राष्ट्र की होती है। जैसे यूनान और मिस्र का प्राचीन राज्य समाप्त हो गया। इसका यह अर्थ तो नहीं कि वहां की भूमि, नदियां, पर्वत, व्यक्ति आदि नष्ट हो गए।**

डाकुओं में जो स्वार्थ के कारण एकता है, क्या उसे भी संस्कृति मानें? उत्तर मिलेगा- 'नहीं।' कुछ देशों की संस्कृति का आधार यद्यपि यह भी है। जैसे अरब में मुसलमानों का संगठन लूट-खसोट के आधार पर ही किया; इसी प्रकार इंग्लैंड भी सामूहिक स्वार्थ के नाम पर ही खड़ा हुआ।

परंतु हमने स्वार्थ के आधार पर एकता खड़ी नहीं की। यही हमारी और दूसरों की संस्कृति में अंतर है। जैसे मां से प्रेम करने के भिन्न-भिन्न आधार हो सकते हैं। इसी प्रकार विवाह के भी भिन्न आधार हो सकते हैं। एक यह कि विवाह दो प्राणियों का एकात्मकता के नाते आगे बढ़ना इसलिए है कि घर की देखभाल के लिए पत्नी मिल जाएगी। इसी प्रकार परिवार में हमारे माता-पिता भी शामिल होंगे। परंतु यूरोप में परिवार में मां-बाप नहीं होते।

जीवन में सभी चीज़ों की ओर देखने की हमारी दृष्टि कुछ भिन्न है। कुछ राष्ट्रों में ईमानदारी को व्यापार के लिए सर्वोत्तम नीति माना जाता है, परंतु हम इसे व्यापार की नीति के रूप में नहीं अपितु जीवन की नीति के रूप में अपनाना चाहते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग रुचि होती है। यह रुचि भिन्नता मूलतः सब प्राणियों में विद्यमान है। इसी प्रकार राष्ट्रों में भी रुचि भिन्नता है, अपनी-अपनी विशेषता है। सबके आधार भिन्न-भिन्न रहते हैं। इसके कारण हमारे देश में भी कुछ चीजें हमें रंजित करती हैं और कुछ नहीं। हमारी विशेष प्रवृत्ति है, जिसके आधार पर हम संगठन करते हैं। वह प्रवृत्ति स्वार्थ की नहीं, निस्स्वार्थ भाव की है। ■

(जून 12, 1959, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दिल्ली)

# नहीं रहे केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार

(22 जुलाई 1959 – 12 नवंबर 2018)

केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार का 12 नवंबर को निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया।

यही नहीं, कैबिनेट ने भी श्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। कैबिनेट की विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि उनके जाने से राष्ट्र ने एक अनुभवी नेता खो दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे 13 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार और समूचे राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।

## जीवन परिचय

श्री अनंत कुमार का जन्म 22 जुलाई 1959 को बेंगलूरू में हुआ था। उन्होने कर्नाटक विश्वविद्यालय, हुबली से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि और कर्नाटक विश्वविद्यालय के अंतर्गत जेएसएस लॉ कॉलेज से कानून में उपाधि प्राप्त की।

श्री अनंत कुमार ने विद्यार्थी कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी की कर्नाटक शाखा के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने। बाद में वे कर्नाटक में पार्टी के अध्यक्ष बने। उनके कुशल प्रबंधन से कर्नाटक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ और पार्टी ने अंततः स्वयं के बलबूते पर सरकार बनाई। वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य सचिव थे।

वे 1996 में बेंगलूरू साउथ से पहली बार लोक सभा के लिये चुने गये थे। 1998 में जब वे दूसरी बार सांसद बने तो वाजपेयी कैबिनेट में उन्हें सबसे युवा मंत्री बनाया गया और नागर विमानन विभाग दिया गया। उन्होंने लोकसभा की प्रतिष्ठित बेंगलूरू साउथ सीट से जीवन के अंतिम दिन तक छह बार प्रतिनिधित्व किया।

अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने पर्यटन मंत्री; संस्कृति, युवा मामले और खेल; शहरी विकास और गरीबी उपशमन; तथा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम किया। वे कई संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी रहे।

श्री अनंत कुमार एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और वे अपने स्वयंसेवी संगठनों के जरिए अनेक सामाजिक सेवा परियोजनाओं का संचालन करते थे। इनमें सरकार की मदद से उपेक्षित स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्यान्न भोजन उपलब्ध कराना, बेंगलूरू की तंग बस्तियों में स्थित विभिन्न स्कूलों के लिये ऐसी मोबाइल यूनिट का संचालन करना जिसमें शैक्षिक उपकरण लगे होते थे, सरकारी स्कूलों को गोद लेना ताकि उनमें पेयजल और अन्य सुविधायें प्रदान की जा सके तथा उपेक्षित वर्गों, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन जैसी गतिविधियां शामिल थी। उन्होने 'ग्रीन बेंगलूरू 1:1' अभियान, शुरू किया, गया जिसका लक्ष्य 1 करोड़ पौधे लगाते हुए बेंगलूरू का हरित क्षेत्र बढ़ाना था। ■

केंद्रीय मंत्री एवं अनुभवी सांसद श्री एच.एन.अनंत कुमार के निधन के बारे में जानकर दु:ख हुआ। यह हमारे देश के सार्वजनिक जीवन को और खासकर कर्नाटक के लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, साथियों एवं असंख्य मित्रों के साथ हैं।

— राम नाथ कोविंद, राष्ट्रपति

संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार के असामयिक निधन के बारे में जानकर मुझे सदमा लगा है और मैं काफी दु:खी हुआ हूं। श्री कुमार छात्र आंदोलन से लेकर संसद तक की जीवन यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण सहकर्मी रहे। वे एक समर्पित राष्ट्रवादी, विख्यात और प्रिय नेता तथा एक विशिष्ट राजनेता थे।
उनके निधन से भारतीय लोकतंत्र और राज्य व्यवस्था को अपूरणीय क्षति हुई है। मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा उनके परिजनों, दोस्तों और प्रियजनों को इस अत्यंत कठिन समय से उबरने की शक्ति और साहस प्रदान करें।

— एम. वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति

अपने महत्वपूर्ण सहयोगी और मित्र श्री अनंत कुमार के निधन से अत्यंत दु:खी हूं। वे एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्होंने कम उम्र में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और कर्मठता तथा दयाभाव के साथ समाज की सेवा करते रहे। उनके अच्छे कार्य के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
मैंने उनकी धर्मपत्नी डॉ. तेजस्विनी जी से बात की और श्री अनंत कुमार के निधन पर संवेदना व्यक्त कीं। इस दुखद घड़ी में उनके पूरे परिवार, दोस्तों और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ॐ शांति।

— श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मैं केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार के असमय निधन से अत्यंत दु:खी हूं। इतनी कम आयु में निधन हम सब और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे गरीबों के लोकप्रिय और जमीन से जुड़े नेता थे। वह एक असाधारण नेता थे, जो कम आयु में सार्वजनिक जीवन में आये और उनमें जबर्दस्त इच्छाशक्ति थी। उन्होंने राजनीति में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

— लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपप्रधानमंत्री

यह जानकर सदमा लगा और बेहद दु:ख हुआ कि हमारे वरिष्ठ साथी अनंत कुमार जी अब हमारे साथ नहीं रहे। वे एक अनुभवी सांसद थे। उन्होंने कई क्षमताओं में देश की सेवा की। लोगों का कल्याण करने का उनका जज्बा और निष्ठा सराहनीय रही। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।

— राजनाथ सिंह, गृहमंत्री

श्री अनंत कुमार का निधन देश, कर्नाटक राज्य, सरकार और मेरी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। यह उनके नेतृत्व का ही फल था कि पार्टी को भारत के दक्षिणी हिस्सों में स्थापित होने के लिए पहला कदम मिला।

— अरुण जेटली, केंद्रीय वित्त मंत्री

अनंत कुमार के निधन के बारे में जानकर दु:खी हूं। वह मेरे छोटे भाई की तरह थे। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत नुकसान है।

— सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध और अत्यंत दुखी हूं। वे एक समर्पित जनसेवक, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, कुशल प्रशासक एवं उत्कृष्ट राजनेता थे।

बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अनंत कुमार लगातार छः बार बंगलोर दक्षिण से लोक सभा सांसद रहे। वे वर्तमान में मोदी सरकार में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री थे। इससे पहले उन्होंने अटल सरकार में भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला था। वे कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वे 2004 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों में प्रभारी के तौर पर भी कुशलतापूर्वक कार्य किया। आपातकाल के दौरान देश मे लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बाल्यकाल से ही वे स्वयंसेवक रहे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। पार्टी, संगठन, विचारधारा और देश के लिए उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।

सौम्य व्यक्तित्त्व, कुशल सांगठनिक क्षमता, ओजस्वी वक्ता और जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले एक जुझारू नेता के रूप में श्री अनंत कुमार सदैव याद किये जायेंगे। श्री अनंत जी का निधन न केवल भारतीय जनता पार्टी, अपितु देश की राजनीति के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। इससे देश के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन में ऐसी रिक्तता आई है जिसकी भरपाई मुश्किल है। उनके निधन से देश ने जनता के लिए काम करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और कुशल संगठनकर्ता को खो दिया है।

दु:ख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ॐ शांति।

— अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

# 1.3 अरब भारतीयों के लिये वित्तीय समावेश अब हकीकत बना: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14-15 नवंबर को सिंगापुर की दो दिवसीय यात्रा की। यात्रा के दौरान श्री मोदी ने न केवल वित्तीय प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े कार्यक्रम 'फिनटेक फेस्टिवल' को संबोधित किया, बल्कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। साथ ही उन्होंने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें थी कीं। इनमें व्यापार, रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति श्री माइक पेन्स के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े कार्यक्रम 'फिनटेक फेस्टिवल' को 14 नवम्बर को संबोधित कर दो दिवसीय सिंगापुर यात्रा की शुरुआत की। श्री मोदी ने सिंगापुर में फिनटेक फेस्टिवल में भारत को निवेश के लिए पसंदीदा जगह बताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों के अनुकूल कई डिजिटल मंच शुरू करने से वित्तीय समावेश 1.3 अरब भारतीयों के लिये हकीकत बन गया है।

श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने भारत में सार्वजनिक सेवाओं के प्रशासन और वितरण को व्यापक रूप से बदल दिया है और नवाचार, आशा तथा अवसर उत्पन्न किये हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ''प्रौद्योगिकी नई दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मकता और शक्ति को परिभाषित कर रही है और जीवन में बदलाव लाने के असीमित अवसर उत्पन्न कर रही है।"

'सिंगापुर फिनटेक शिखर सम्मेलन' में प्रधानमंत्री ने कहा, ''इसने कमजोरों को अधिकार संपन्न बनाया है और हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाया है।" श्री मोदी ने कहा कि फेस्टिवल भारत में चल रही वित्तीय क्रांति की स्वीकृति है।

उन्होंने कहा, ''यह वित्त और प्रौद्योगिकी का एक कार्यक्रम है, यह एक उत्सव भी है। यह विश्वास का जश्न भी है। नवाचार की भावना में विश्वास और कल्पना की शक्ति। युवा शक्ति और उनके बदलाव लाने के जुनून में विश्वास। विश्वास, दुनिया को बेहतर स्थान बनाने का।" श्री मोदी ने कहा कि यह फेस्टिवल युवाओं को समर्पित है, जिनकी

नजर दृढ़ता से भविष्य पर टिकी हैं। उन्होंने कहा, ''वित्तीय समावेश 1.3 अरब भारतीयों के लिये हकीकत बन गया है। हमने कुछ ही वर्षों में 1.2 अरब से अधिक बायोमीट्रिक पहचान- आधार या फाउंडेशन बनाए हैं।" उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का चरित्र बदल रहा है।

श्री मोदी ने कहा, ''भारत विविधतापूर्ण परिस्थितियों और चुनौतियों का देश है। हमारे समाधान भी विविधता भरे होने चाहिए। हमारा डिजिटलीकरण एक सफलता है, क्योंकि हमारे भुगतान उत्पाद सभी की जरूरतें पूरी करते हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा, ''भारतीय कहानी फिनटेक के छह बड़े फायदों को दिखाती हैः पहुंच, समावेशन, संपर्क, जीवन सुगमता, अवसर और जवाबदेही।" फेस्टिवल को संबोधित करने वाले श्री मोदी विश्व स्तर के पहले नेता हैं। उन्होंने कहा, ''हम प्रौद्योगिकी द्वारा लाए गए एक ऐतिहासिक परिवर्तन के युग में हैं। डेस्कटॉप से क्लाउड, इंटरनेट से सोशल मीडिया, आईटी सेवाओं से इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक हमने कम समय में काफी लंबी दूरी तय की है।"

## हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शांत, समृद्धि के लिये प्रतिबद्ध है भारत: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को सिंगापुर में 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया और एक शांत एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये देश की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय भागीदारी तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में संबंधों का विस्तार किए जाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी पांचवीं बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन की 2005 में शुरुआत होने के बाद से ही भारत इसमें भाग ले रहा है। श्री मोदी ने ट्वीट किया, ''पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मैंने सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय तालमेल तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को विस्तृत करने के बारे में अपने विचार साझा किया। मैंने शांत एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिये भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।"

इसके सदस्य देशों में 10 आसियान देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमा, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शांत, खुला एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र, मजबूत होते समुद्री सहयोग और संतुलित क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का भारतीय दृष्टिकोण दोहराया।"

श्री मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन रीट्रीट से पहले जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे समेत अन्य देशों के नेताओं के साथ बातचीत की। श्री मोदी इससे पहले आसियान-भारत शिखर बैठक में भाग लिया। इसमें उन्होंने सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के लिये समुद्री सहयोग और व्यापार के केंद्रीकरण की जरूरत को रेखांकित किया।

श्री मोदी ने ट्वीट किया, ''आसियान-भारत शिखर बैठक में आसियान देशों के नेताओं से बातचीत हुई। हमें इस बात की खुशी है कि आसियान के साथ संबंध मजबूत हैं और शांत एवं समृद्ध विश्व के लिये हम योगदान दे रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कैडेट आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत सिंगापुर गये एनसीसी के कैडेट दल से भी मुलाकात की। उन्होंने इस पर ट्वीट किया, ''युवा साथियों के साथ सुंदर समय। मैंने कैडेट आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत सिंगापुर आये एनसीसी कैडेटों के साथ मुलाकात की। उन्होंने यादगार सीख एवं अनुभवों को मेरे साथ साझा किया।" ■

# विमुद्रीकरण का प्रभाव

अरुण जेटली

आज विमुद्रीकरण को दो साल हो गए हैं। अर्थव्यवस्था को निर्दिष्ट आकार देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है और विमुद्रीकरण इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने सबसे पहले भारत के बाहर संचित काले धन पर प्रहार किया। इन संपत्ति धारकों को दंडात्मक कर भुगतान के बाद इस धन को स्वदेश वापस लाने का एक मौका दिया गया। जो लोग ऐसा करने में विफल रहे उन पर काला धन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। वहीं सरकार को प्राप्त सभी विदेशी खातों और संपत्तियों के विवरण पर गौर करने के बाद संबंधित नियम-कायदों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

रिटर्न दाखिल करने में सुविधा और कर दायरा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के लिए किया गया है।

देश के कमजोर तबकों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सके, इसके लिए वित्तीय प्रणाली से उनको जोड़ा गया जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। जन-धन खातों की बदौलत ज्यादातर लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गए हैं। आधार के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी सहायता प्रणाली का प्रत्यक्ष लाभ सीधे गरीबों के बैंक खातों में पहुंचे। अप्रत्यक्ष करों के मामले में जीएसटी ने यह सुनिश्चित किया है कि कर प्रक्रियाएं आसान बनें। अब कर प्रणाली के दायरे में आने से बचना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

## नकदी की भूमिका

भारत की अर्थव्यवस्था में नकदी का चलन बेहद ज्यादा था। नकद से किए जाने वाले सौदों में लेन-देन करने वालों के बारे में पता नहीं चल पाता है। इससे बैंकिंग प्रणाली की अनदेखी होती है और नगदी में सौदे करने वाले लोग टैक्स चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। विमुद्रीकरण ने कैश रखने वाले लोगों को बैंकों में नकद राशि जमा करने के लिए विवश किया। इस दौरान भारी-भरकम नकद राशि जमा की गई और इसके साथ ही यह रकम जमा करने वाले लोगों की पहचान भी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 17.42 लाख खाताधारक संदिग्ध पाए गए। इनसे ऑनलाइन जानकारियां प्राप्त की गई हैं। नियम-कायदों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। बैंकों में बड़ी मात्रा में राशि जमा होने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में सुधार हुआ। इस धन का एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंडों में निवेश किया गया और यह राशि औपचारिक प्रणाली का हिस्सा बन गई।

## गलत तर्क

विमुद्रीकरण की आलोचना कुछ गलत जानकारियों के आधार पर यह कहते हुए की जा रही है कि लगभग पूरी नकद राशि बैंकों में जमा कर दी गई है। नकद राशि का भंड़ारण विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं था। इस राशि को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना और इसका संचय करने वाले लोगों को कर के दायरे में लाना इसका व्यापक उद्देश्य था। भारत को नकद लेन-देन से डिजिटल लेन-देन की ओर ले जाने के लिए व्यापक बदलाव की आवश्यकता थी। इसका असर कर राजस्व में बढ़ोत्तरी और कर दायरे को व्यापक करने में निश्चित ही देखा जाएगा।

## डिजिटलीकरण पर प्रभाव

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी जिसके माध्यम से दो मोबाइल धारकों के बीच त्वरित भुगतान किया जा सकता है। जहां अक्टूबर, 2016 में इस माध्यम के जरिए 0.5 अरब रुपये का लेन—देन हुआ था, वहीं सितंबर, 2018 तक आते आते यह राशि 598 अरब रुपये हो गयी है। यूपीआई तकनीक से त्वरित भुगतान करने के लिए एनपीसीआई ने भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) नामक ऐप विकसित किया है। वर्तमान में इसका उपयोग 1.25 करोड़ लोगों द्वारा किया जा रहा है। भीम ऐप से लेन-देन की कुल राशि सितंबर, 2016 के 0.02 अरब रुपये से बढ़कर सितंबर, 2018 में 70.6 अरब रुपये हो गयी है। जून, 2017 में यूपीआई प्रणाली के कुल लेन-देन में भीम ऐप की हिस्सेदारी लगभग 48 प्रतिशत रही।

रुपे कार्ड का उपयोग प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स दोनों के लिए किया जाता है। इसके जरिये विमुद्रीकरण से

**देश के कमजोर तबकों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सके, इसके लिए वित्तीय प्रणाली से उनको जोड़ा गया जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। जन-धन खातों की बदौलत ज्यादातर लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गए हैं। आधार के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी सहायता प्रणाली का प्रत्यक्ष लाभ सीधे गरीबों के बैंक खातों में पहुंचे। अप्रत्यक्ष करों के मामले में जीएसटी ने यह सुनिश्चित किया है कि कर प्रक्रियाएं आसान बनें। अब कर प्रणाली के दायरे में आने से बचना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।**

पहले पीओएस लेन-देन का आंकडा 8 अरब रुपये था, जबकि सितंबर 2018 में यह बढ़कर 57.3 अरब रुपये हो गया। वहीं विमुद्रीकरण से पहले जहां रुपे कार्ड से ऑनलाइन भुगतान 3 अरब रुपये था, जबकि सितंबर 2018 में यह बढ़कर 27 अरब रुपये हो गया है।

स्वदेश में विकसित भुगतान प्रणाली यूपीआई और रुपे कार्ड के आने से अब वीजा और मास्टरकार्ड भारत के बाजार में अपनी हिस्सेदारी गंवा रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्डों के जरिये किये गये कुल भुगतान में यूपीआई और रुपे कार्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है।

की संख्या 6.86 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष, 31-10-2018 तक, 5.99 करोड़ लोगों ने रिटर्न जमा किया है जो कि पिछले वर्ष इस तिथि की तुलना में 54.33 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष 86.35 लाख नए करदाता कर प्रणाली से जुड़े हैं।

मई 2014 में, जब वर्तमान सरकार चुनी गयी थी तब आयकर रिटर्न जमा करने वालों की कुल संख्या 3.8 करोड़ थी, लेकिन मौजूदा सरकार के पहले चार वर्षों में ही यह संख्या 6.86 करोड़ हो गयी है। हम मान रहे है कि सरकार का पांच वर्षों का कार्यकाल खत्म

**विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने से नकद लेनदेन पर बड़े पैमाने पर लगाम लगी है। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि दिखी जा रही है। अर्थव्यवस्था के इस औपचारिकरण ने करदाताओं की संख्या जीएसटी पूर्व शासन में 6.4 मिलियन से बढ़ाकर जीएसटी के बाद के शासन में 12 मिलियन कर दी है। इस दौरान कर दायरे में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खपत में भी बढ़ोत्तरी देखी गई है। इसने अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इससे केंद्र और राज्य दोनों को फायदा हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य प्रत्येक वर्ष टैक्स से प्राप्त राजस्व में 14% की वृद्धि हुई है।**

## प्रत्यक्ष कर पर प्रभाव

व्यक्तिगत कर दाताओं पर विमुद्रीकरण का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा वित्तीय वर्ष 2018-19 (31-10-2018 तक) कर दाताओं की संख्या में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कॉर्पोरेट कर दाताओं के आंकड़ें में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। विमुद्रीकरण से पहले जहां प्रत्यक्ष कर संग्रह में क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं विमुद्रीकरण के बाद के दो सालों में यह दर 14.6 प्रतिशत (2016-17 में विमुद्रीकरण के प्रभाव से पहले वर्ष का हिस्सा भी शामिल है) और 18 प्रतिशत रही।

वर्ष 2017-18 में टैक्स रिटर्न भरने वालों होते—होते टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।

## अप्रत्यक्ष कर पर प्रभाव

विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने से नकद लेनदेन पर बड़े पैमाने पर लगाम लगी है। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि दिखी जा रही है। अर्थव्यवस्था के इस औपचारिकरण ने करदाताओं की संख्या जीएसटी पूर्व शासन में 6.4 मिलियन से बढ़ाकर जीएसटी के बाद के शासन में 12 मिलियन कर दी है। इस दौरान कर दायरे में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खपत में भी बढ़ोत्तरी देखी गई है। इसने अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इससे केंद्र और राज्य दोनों को फायदा हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य प्रत्येक वर्ष टैक्स से प्राप्त राजस्व में 14% की वृद्धि हुई है। वास्तविकता यह है कि निर्धारकों के लिए अब अपने व्यापार के टर्नओवर की घोषणा करना जरूरी है, जो न केवल अप्रत्यक्ष कर की गणना को प्रभावित करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनसे प्राप्त आयकर का खुलासा भी आकलन में हो सके। 2014-15 में, जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का अनुपात 4.4 प्रतिशत था। जीएसटी लागू होने के बाद यह कम से कम 1 प्रतिशत बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया है। छोटे करदाताओं को 97,000 करोड़ रुपये की वार्षिक आयकर राहत देने और जीएसटी दाताओं के लिए 80,000 करोड़ रुपये की राहत देने के बावजूद कर संग्रह बढ़ा है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की दर घटी है, लेकिन कर संग्रह बढ़ा है। मौजूदा टैक्स दरों में फेरबदल और विस्तार किया जा रहा है। 334 वस्तुओं पर टैक्स की दरें जो पहले 31 प्रतिशत थी जीएसटी लागू होने के बाद उनकी टैक्स दरों में कटौती देखी गई है। सरकार ने इन संसाधनों का उपयोग बुनियादी ढांचा निर्माण, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत को बेहतर बनाने के लिए किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज हमारे गांव सड़क से जुड़े रहे है, हर घर में बिजली पहुंची है, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 92 प्रतिशत हो गई है, जनता को अपने घर मिले हैं और 8 करोड़ गरीबों के घरों में खाना पकाने के लिए गैस कनेक्शन दिए गए है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत दस करोड़ परिवार स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, जनता को सब्सिडी वाला खाद्य वस्तुओं प्रदान करने के लिए 1,62,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वहीं किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी चल रही है। यह अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण ही है जिसके कारण 13 करोड़ उद्यमियों को मुद्रा ऋण प्राप्त हुआ है और केवल कुछ हफ्तों में ही सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया। अंततः ओआरओपी भी लागू हो गया। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त मंत्री है)

# सार्वभौमिक विद्युतीकरण: सरकार ने जो कहा वह किया

आर के सिंह

हमने देश की जनता को 24 घंटे बिजली देने का एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है और जिस हाल में हमें यह व्यवस्था मिली थी, उसमें केवल घरों तक बिजली के तार पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि एक विश्वसनीय आपूर्ति तंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी तैयार करना था। लेकिन आज हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर हैं और यह बदलाव ऐसा है जैसे दुनिया में पहले कहीं नहीं देखा गया है।

हमने 28 अप्रैल 2018 को 100% गांव तक बिजली पहुंचाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जो सार्वभौमिक विद्युतीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह लक्ष्य केवल शेष 18,500 गांवों को बिजली नेटवर्क से जोड़ने का नहीं था, बल्कि आजादी के 70 वर्ष के बाद भी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर गरीब परिवारों तक उम्मीद की एक नयी किरण पहुंचाने जैसा था। इसमें शामिल चुनौतियां बड़ी थीं और इन चुनौतियों के चलते ही ये गांवों आज तक रोशन नहीं हो पाए। इनमें से अधिकतर गांव दूरदराज पहाड़ी इलाकों, वन क्षेत्रों और एलडब्ल्यूई गतिविधियों से गंभीर रूप से प्रभावित थे। वहीं ऐसे दुर्गम इलाकों तक उपकरणों और मजदूरों को पहुंचाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसकों पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। लेकिन हम रुके नहीं और निरंतर एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही लगभग 350 गांव जिसमें अरुणाचल प्रदेश (272), जम्मू-कश्मीर (54), मेघालय (9) और मणिपुर (12) जहां उपकरणों और अन्य जरूरी साजो-सामान को पहुंचाने के लिए लगभग 10 दिनों तक पैदल चलने की आवश्यकता पड़ी। जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांवों तक सामग्री को हेलीकॉप्टर द्वारा भी पहुंचाया गया। वहीं 2762 रिमोट गांवों में जहां ग्रिड नेटवर्क का विस्तार संभव नहीं था, वहां सौर आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से बिजली को पहुंचाया गया। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 7614 एलडब्ल्यूई गांवों के विद्युतीकरण में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन गांवों तक बिजली पहुंचने से इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। हमने यह लक्ष्य निर्धारित तिथि से पहले हासिल किया है, जिससे हमे बेहद संतुष्ट है। इस कार्यक्रम ने प्रभावी सहकारी संघवाद का एक उम्दा उदाहरण भी स्थापित किया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, वितरण कंपनियों और प्रशासन ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम किया।

अब हमारा अगला कदम था, प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से सितंबर 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' - सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए मार्च 2019 का लक्ष्य रखा गया। इस समय-सीमा के अंदर लक्ष्य को हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। जैसा कि इस योजना के नाम में ही अंतर्निहित है कि 'सहज' यानी सरल / आसान / प्रयासहीन और 'हर घर' यानी सार्वभौमिक विद्युतीकरण, हम इस योजना की इन विशेषताओं को लेकर आगे बढ़े। इस पैमाने पर एक लक्षित कार्यक्रम दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। इस कार्यक्रम की गति और नवाचार के मामले में इसकी प्रगति अनुकरणीय है। हम हर दिन एक लाख घरों को रोशन कर रहे हैं। इन घरों में जब बिजली पहुंचती है तो वहां मौजूद लोगों के चेहरे की खुशी को शब्दों मे बयान नहीं किया जा सकता। हमने 19 नवंबर 2018 तक सौभाग्य योजना (जो अक्टूबर 2017 में शुरू हुई) के तहत 2 करोड़ परिवारों को रोशनी किया है।

विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत सप्लाई के लिए देश के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना, वितरण के ढांचे को मजबूत करना, मीटरिंग, आईटी और स्वचालन जैसे विषय भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीजीजीवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन योजनाओं के तहत 1,40,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं को शुरू किया जा चुका है। वहीं इन योजनाओं के तहत 1204 उप—स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा 1601 उप—स्टेशनो की क्षमता का विस्तार, 1,61,101 ट्रांसफार्मरों की स्थापना, 1,11,734 किमी एचटी लाइनों और 98028 किलोमीटर एलटी लाइन का कार्य पूरा किया जा चुका है।

इन योजनाओं के तहत उठाए गए कदमों के साथ ही उज्जवल डिस्कॉम एशोरेनश

योजना (यूडीएई) के तहत अपनाए सुधारों के चलते 24 घंटे बिजली आपूर्ति के हमारे लक्ष्य को बल मिल रहा है। यूडीएई योजना के लागू होने के बाद (i) एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस (एटी और सी) 20.77% से घटकर 18.72% पर आ गया है। (ii) एसीएस-एआरआर का (आपूर्ति की औसत लागत - औसत राजस्व प्राप्ति) अंतर 60 पैसे/यूनिट से घटकर 17 पैसा/यूनिट पहुंच गया है। (iii) ब्याज पर 31,800 करोड़ रुपए की बचत और क्षति से होने वाले नुकसान 51575 करोड़ रुपये से घटकर 15132 करोड़ रुपये हो गया है। कोयले, माल ढुलाई और अन्य लागतों में वृद्धि के बावजूद बिजली की कीमतों को लगभग स्थिर रखने के लिए एनटीपीसी और अन्य प्रमुख कंपनियों को बधाई दी जानी चाहिए।

सरकार के निरंतर प्रयासों के चलते विश्व बैंक की 'ईज ऑफ़ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी' रैंकिग में आज हम 24वें स्थान पर पहुंच गए है, जबकि साल 2014 में हम 111वें स्थान पर थे। यह इस दिशा में एक बड़ी छलांग है और सरकार के परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है।

हम 'वन नेशन वन ग्रिड' के लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच रहे है। पिछले साढ़े चार सालों में ग्रिड निर्माण की गति प्रति वर्ष 24,908 किलोमीटर रही, जबकि इसके पहले के वर्षों में यह रफ्तार केलव 4385 किमी प्रति वर्ष थी। इसका निमार्ण देश भर में बिजली वितरण सुनिश्चित करेगा। वर्ष 2014-18 के दौरान 2.96 लाख एमवीए ट्रांसफार्मेशन कैपेसिटी को मौजूदा तंत्र में जोड़ा गया है। वहीं, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया ने इस प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने का काम किया है।

इस तंत्र में प्रति दिन एक लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने के साथ इन महीनों में बिजली की मांग 10% से अधिक की दर से बड़ी है, जिसका सीधा असर हमारी आर्थिक प्रगति पर दिखता है। इस क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे है वह बेजोड़ है, लेकिन अभी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसको लेकर हमारी सोच स्पष्ट है और हमारा संकल्प भी दृढ़ है। हमारा अनुमान हैं कि अभी लगभग 50 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचाना बाकी है और यदि हम वर्तमान गति से इस काम को अंजाम देते हैं तो 100% घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगभग 50 दिन का समय और लगेगा। दुनिया इस दौरान बड़े ही आश्चर्य और प्रशंसा के साथ हमारी प्रगति को देखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हमारे इस प्रयास को वर्ष की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक कहा है।

देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाना भी स्वभाविक है। पिछले 4 वर्षों के दौरान मौजूदा उत्पादन क्षमता में 1 लाख मेगावाट की वृद्धि की गई है। इससे ऊर्जा की कमी को 4.2% से घटाकर लगभग शून्य (0.7%) तक लाने में हम कामयाब हुए है और पहली बार अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के साथ ही भारत बिजली निर्यातक देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। इस क्रम में हमने 7203 एमयू बिजली निर्यात करके नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसियों की मदद की है।

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हमारा उत्पादन स्वच्छ रहे, इसके लिए हमने 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 175 जीडब्ल्यू क्षमता हासिल करने का एक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें 100 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा और 60 जीडब्ल्यू पवन ऊर्जा का उत्पादन शामिल है। अक्षय ऊर्जा की कुल क्षमता पिछले साढ़े सालों में दोगुनी हो गई है, जो 34,000 मेगावॉट से बढ़कर 72,000 मेगावॉट पर पहुंच गई है। वहीं पिछले 4 वर्षों में सौर ऊर्जा की क्षमता में 8 गुना का इजाफा देखा गया है। हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सही दिशा में चले रहे हैं।

एक ओर जहां हम बिजली उत्पादन में निरंतर वृद्धि कर रहें है, वहीं दूसरी ओर हमें इसके सही और दक्षतापूर्ण उपयोग पर भी बल दे रहे है। इस दिशा में सरकार की नीतियों के माध्यम से उपभोगताओं को जगरूक करने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उजाला, स्टार लेबलिंग, एनर्जी कन्सेर्वटिव बिल्डिंग कोड, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड(पीएटी) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीएटी कार्यक्रम के पहले चक्र के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है और हमें उम्मीद है कि इस कामयाबी को अगले चक्र में भी कायम रखा जाएगा। ■

(लेखक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है)

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

# कांग्रेस ने झूठ बोलने का रास्ता चुना है और हमने गरीब जनता की सेवा करने का: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में विशाल जन-सभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से प्रदेश के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रचंड बहुमत से पुनः श्री रमण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। इससे पहले सभा में मंच पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सरगुजा का पारंपरिक वाद्ययंत्र मांदर देकर स्वागत किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के पहले चरण के चुनावों के दौरान देश ने देखा कि एक तरफ तो नक्सली लोगों की हत्याएं कर रहे थे, खून बहा रहे थी, वहीं, दूसरी तरफ लोग इस सबके बीच विश्वास के साथ अपने-अपने घरों से निकल कर मतदान कर रहे थे। नक्सलियों ने अंगुलियां काटने की धमकी दी थी, लेकिन बस्तर के लोगों ने भारी मतदान करके दिखाया। इतना भारी मतदान करने के लिए बस्तर के लोगों का गौरवगान किया जाना चाहिए। इससे प्रेरणा लेकर आगामी 20 नवंबर के दिन आप और भारी मतदान कर लोकतंत्र को विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जब अंबिकापुरवासियों ने सभा के लिए लाल किला के प्रतिकृति बनाई थी, तो तब दिल्ली में बैठी सरकार की नींद उड़ गई थी। पहले चरण की वोटिंग को देखकर भी कांग्रेस की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबिकापुर को बदनाम कर दिया उनसे हिसाब मांगने का समय आ गया है, उन्हें इस चुनाव में चुन-चुनकर घर भेजने का समय आ गया है।

श्री मोदी ने कहा कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठ गया, यह बात कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को ही नहीं समझ पा रही है। यदि वे लोकतंत्र की समझ रखते तो उन्हें समझ आता कि देश की राजनीति एक परिवार तक ही सीमित नहीं है। यदि कांग्रेस परिवारवाद से बाहर निकल कर किसी सामान्य व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, तब यह समझ आएगा कि नेहरू जी ने इस लोकतंत्र की आधारशिला किस आधार पर रखी थी। देश में एक चाय वाले का प्रधानमंत्री बनना देश की जनता के आशीर्वाद से हुआ। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। कांग्रेस को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि यदि पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक मूल्य इतने ही मजबूत हैं, तो कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर के किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को पांच साल के अध्यक्ष बना कर दिखाए।

नोटबंदी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां बैठा एक भी व्यक्ति नोटबंदी के लिए रो नहीं रहा है, लेकिन एक परिवार नोटबंदी को लेकर लगातार रोए ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के

जरिए हमने तय किया कि देश से लूटा गया धन वापस देश की जनता को मिले, लेकिन कांग्रेसी इस बात पर रो रहे हैं। चाय वाला पैसे चुरा ले गया, ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा कहकर वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनता का धन जो कुछ लोगों की बोरियों में बंद था, अब बाहर निकल रहा है और आने वाले समय में यह आम जनता के काम आएगा। गरीबों के लिए घर बनाने, उन्हें राशन मुहैया कराने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम इस धन को खर्च कर रहे हैं। सरकार महिलाओं के नाम पर मकान दे रही है, ताकि वह पूरे सम्मान और गर्व के साथ जीवन जी सके।

श्री मोदी ने कहा कि देश ने कांग्रेस की एक नहीं, चार-चार पीढ़ियों को परखा है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने कभी भी देश की जनता को अपनी चार पीढ़ियों के कामकाज का हिसाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देश और प्रदेश के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि चार पीढ़ियों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को खुद हिसाब देना चाहिए, लेकिन वे 4 साल वालों से जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए अजित जोगी के तीन साल और दिग्विजय सिंह के दो साल के कार्यकाल में 60 फीसदी वादे पूरे नहीं किए, लेकिन चुनाव आते ही कांग्रेस फिर से तमाम तरह के वादों के पिटारे खोल देती है, उन्हें मालूम है कि वे आने वाले तो हैं नहीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब केन्द्र में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना क्योंकि जनता का विश्वास हम पर था। आपने बीजेपी को चुना, यह आपका विश्वास था हम पर।

**कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलने का रास्ता चुना है, हमने गरीब जनता की सेवा करने का रास्ता चुना है। कांग्रेस भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास के मिशन पर काम करती है।**

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अनेक वर्षों तक तेलंगाना की मांग ठुकराती रही, तेलंगाना का आंदोलन करने वालों पर गोलियों चलाती रही लेकिन कभी संसद में चर्चा नहीं की। जब राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बारी आयी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के हकों को बिना सुने ही फैसला कर दिया।

श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना तेरे-मेरे के, बिना अपने-पराए के, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना एक मंत्र को लेकर चल रही है "सबका साथ, सबका विकास।

श्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलने का रास्ता चुना है, हमने गरीब जनता की सेवा करने का रास्ता चुना है। कांग्रेस भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास के मिशन पर काम करती है। उन्होंने कहा कि अकेले 33 करोड़ बैंक खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए हैं। जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कभी, बैंक जाने की एक चायवाले ने उनके बैंक अकाउंट खुलवाए हैं और उनके लिए बैंकों के द्वार खोले हैं। कांग्रेस पार्टी को नींद नहीं आ रही है कि हमारे परिवार की विरासत, हमारी राजगद्दी को एक चाय वाला कैसे चुरा ले गया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार कैसी होती है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र एवं राज्य सरकारों ने यह करके दिखाया है। कांग्रेस के जमाने में गैस कनेक्शन राजदरबारियों को मिलता था, हमने देश के गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए मेरे सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानी ही मेरा परिवार है, इनके सुख हमारे सुख हैं, इनका दुख मेरा दुख है। इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लाए, किसानों के फसल के समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना किया और हर योजना के केंद्र में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं का ध्यान रखा।

उन्होंने कहा कि अंबिकापुर की जनता को जिले की सभी सीटों पर से कांग्रेस के प्रत्याशियों हराना होगा क्योंकि बार-बार से उनके झूठे वादों से जनता भी अब परेशान हो चुकी है। जनसभा में सरगुजा संभाग की विधानसभा सीटों के भाजपा उम्मीदवार रामविचार नेताम, विजय प्रताप, अनुराग सिंह, रजनी त्रिपाठी, प्रो गोपाल राम भगत, विजय नाथ सिंह और राम किशुन सिंह भी मौजूद थे। ■

# राज्य में लगातार चौथी बार कमल खिलने वाला है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव (जशपुर), चपले खरसिया (रायगढ़) और धमतरी में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से 'नवा छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़'' बनाने के लिए श्री रमण सिंह के नेतृत्व में दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता के प्यार और आशीर्वाद से निश्चित है कि राज्य में लगातार चौथी बार कमल खिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की विकास-गाथा को आगे बढ़ाने के लिए श्री रमण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का समाधान कर जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस जनता को समस्याओं में झोंकने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी एटीएम है जिसमें सवाल डालने पर केवल झूठ ही बाहर आता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने झूठे वादे करने के सिवाय जनता की भलाई के लिए कभी कोई कार्य किया ही नहीं।

नक्सलवाद पर एक कांग्रेस नेता के बयान की तीखी आलोचना करते हुए श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद को क्रांति का माध्यम समझने वाली पार्टी छत्तीसगढ़ का कोई भला नहीं कर सकती। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नक्सलवाद में क्रांति दिखाई देती है। बम धमाकों में क्रांति दिखाई पड़ती है लेकिन हमें गरीब के घर में बिजली, भोजन और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में क्रांति दिखाई देती है। उन्होंने सभा में उपस्थित जनता से पूछते हुए कहा कि राज्य से नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए या नहीं तो जनता ने एक स्वर में उद्घोष किया कि नक्सलवाद का जड़ से खात्मा होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में अर्बन माओवादी पकड़े गए, तो कांग्रेस पार्टी इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताने लगी लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह मालूम होना चाहिए कि जवानों को मारना, रेल की पटरियों को उखाड़ना, सड़कों को तोड़ना, पत्रकारों की हत्या करना, देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचना और बम धमाके करना कभी भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को संरक्षण दिया, जबकि रमण सिंह सरकार इसे ख़त्म कर राज्य में विकास की बयार लाना चाहती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों के लिए काम करने वाली सरकारें कैसी होती है, यह मोदी सरकार एवं रमन सिंह सरकार ने कर के दिखाया है और प्रदेश की जनता भी इसे बखूबी महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे पहला बिजली सरप्लस राज्य बना है। सीमेंट उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ काफी आगे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इन्फ्रास्ट्रक्चर - सभी क्षेत्रों में रमन सिंह सरकार ने प्रगति के नए आयामों को छुआ है। उन्होंने कहा कि श्री रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास कर राज्य को 'बीमारू' से 'विकसित' प्रदेश बनाया है, अगले पांच सालों के लिए जनता का आशीर्वाद मिलने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार 'नवा छत्तीसगढ़' के संकल्प को साकार करने के लिए समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसका काम है - झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार-बार बोलना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसने श्री रमन सिंह जी के नेतृत्व में 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त व विकासयुक्त एक प्रगतिशील राज्य बनाया है। साथ ही, राज्य को बिजली और सीमेंट उत्पादन के हब के रूप में विकसित किया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं गरीबी हटाओ, राहुल गांधी कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं बेरोजगारी हटाओ, राहुल गांधी कहते हैं मोदी हटाओ। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मोदी फोबिया हो गया है। ■

# हमारा मंत्र है- बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई, किसानों के लिए सिंचाई और बुजुर्गों के लिए दवाई: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के झाबुआ और रीवा में विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और और मध्य प्रदेश के साथ अन्याय करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कठघरे में खड़ा करते हुए उस पर करारा प्रहार किया।

श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के 55 साल की बदहाली वाले दिन फिर से राज्य में नहीं आने देगी। राज्य की जनता ने पहले ही श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने का मतलब होता है भाई-भतीजावाद, जातिवाद का जहर और सम्प्रदायवाद की लड़ाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद, सम्प्रदायवाद और झूठे वादों के दम पर जनता को गुमराह कर शासन किया है, लेकिन कभी भी देश की गरीब जनता को सशक्त बनाने के कोई उपाय नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 सालों तक रिमोट कंट्रोल वाली कांग्रेस सरकार ने मध्यप्रदेश के विकास को बाधित करने की हरसंभव कोशिश की। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है, जो मध्य प्रदेश की जनता के सपनों साकार करने प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को अंधेरे की ओर धकेलने का महापाप किया। कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति को जन्म दिया, जिसने भारतवर्ष को तबाह कर के रख दिया। उन्होंने कहा कि हमने विकास और सोचने का रास्ता बदल दिया है। पहले लोग अंधेरे में जीने की आदत थी लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार आए जो फिर आप लोगों को अंधेरे की तरफ लेकर जाए? मध्य प्रदेश को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो वहां के कल्याण के बारे में नहीं सोचती हो। उन्होंने प्रदेश की जनता से राजनीतिक पार्टियों के दावों को कसौटी पर परखने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किये गए कार्यों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस क 50 साल के शासन में नहीं हुआ, उसे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने 15 साल में कर के दिखा दिया है। जो काम आजादी के 70 सालों में देश में नहीं हुआ, उसे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में कर दिखाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। यह चुनाव किसी दल का भाग्य निर्धारित करने के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की जनता का भाग्य बदलने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज किसानों की बात करती है, लेकिन कांग्रेस बताये कि 15 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट कांग्रेस की सरकार में क्यों अटकते रहे? उन्होंने कहा कि देश में हमने ऐसे 99 प्रोजेक्ट्स खोज-खोज कर बाहर निकाले और उन योजनाओं पर काम शुरू किया जो कांग्रेस राज में फाइलों में गुम थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक ही काम रह गया है - झूठ बोलो, बार-बार बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और योजनाओं को अटकाते, लटकाते और भटकाते रहो। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन आज कर्नाटक सरकार के एक साल पूरे होने के बावजूद किसानों का ऋण तो माफ़ हुआ नहीं, हां, किसानों को जेल भेजने के वारंट जरूर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बहुत बड़ा किसान घोटाला हुआ जो कांग्रेस के कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलिकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, टूजी घोटाला जैसे तमाम अनगिनत घोटालों में कहीं गुम हो गई। उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल वाली कांग्रेस सरकार के समय किसानों पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, लेकिन किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये भी माफ़ नहीं हुए। जब यह चोरी पकड़ी गई तो कांग्रेस सरकार ने नया खेल खेला, उसने लगभग 7 करोड़ लोगों को सर्टिफिकेट ही नहीं दिया और किसानों की ऋण माफी अटक गई

श्री मोदी ने कहा कि विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी सरकार है और कांग्रेस अंधेरे की पर्यायवाची है। देश में जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, विकास तेज गति से हुआ है और

समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आज योजनायें बनती भी हैं, और जमीन पर उतरती भी हैं जबकि कांग्रेस सरकारों में योजनायें सरकारी फाइलों की धूल ही फांकती रहती थी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए होती है और केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई लगभग सभी योजनाओं के केंद्र में देश के गरीब ही हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के अंतर्गत हमने देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत दी है। एक नया हौसला और नया विश्वास दिया है। उन्होंने कहा कि पहले बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खुलते नहीं थे, लोन के लिए जमीन, घर, खेत गिरवी रखना पड़ता था, जबकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऋण के लिए गारंटी का चक्कर ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 करोड़ लोन लगभग बिना गांरटी के मंजूर किए हैं जिसमें से लगभग 70 फीसदी वे लोग हैं जिन्हें पहली बार बैंकों से पैसा मिला है। आज वे अपने पैरों में खड़े भी हो रहे हैं और दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। इस योजना ने सुदूर इलाकों के नौजवानों के हाथों में ताकत देने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की तुलना में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के विकास कार्यों का तुलनात्मक ब्यौरा देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में कांग्रेस सरकार की तुलना में कई गुना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि हमने अपने सामने जन-कल्याण के कई लक्ष्य रखे हैं। हमने सपना देखा है कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे होंगे, तब देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना घर होगा। किसानों की आय दुगुनी होगी। हर गांव पक्के सड़क से जुड़ा होगा और हर घर में बिजली, पानी, गैस और शौचालय होगा। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर के महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश की जनता के सपनों का मध्य प्रदेश बनाना है, महान क्रांतिकारी और देश के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत बनाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के जमाने में विकास का मतलब था मिट्टी डालो और उसको सड़क समझो, आज उस जमाने को हमने बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र है- बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई, किसानों के लिए सिंचाई और बुजुर्गों के लिए दवाई।

श्री मोदी ने कहा कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस के राज के कारण ऐसा भ्रष्टाचार फैला कि नोटबंदी जैसी कड़वी दवा का उपयोग करना पड़ा, ताकि गरीबों को लूट कर ले जाया गया पैसा देश के खजाने में वापस आये और गरीबों के काम आये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तब भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद कर दिया। इससे निपटने के लिए हम पहले तकनीकी लेकर आए। इससे ट्रांसपेरेंसी आई। उन्होंने आगे कहा कि आज उस पैसे से गरीबों के लिये जो घर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। आज गरीबों का पैसा देश के गरीबों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में काम आ रहा है, तो इससे कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को परेशानी हो रही है।

आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आयुष्मान योजना लाए जिससे देश के गरीब भी अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। गरीबों के इलाज और ऑपरेशन का पांच लाख रुपये तक का सालाना खर्चा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि देश के सवा सौ करोड़ भारतवासी ही मेरे परिवार हैं, उनके सपने ही मेरे सपने हैं। जब तक ग़रीबों को समाज में बराबरी का स्थान न दिला दूं, उनके जीवन में बदलाव न ले आऊं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ■

# कांग्रेस का न कोई नेता है, न नीति और न नीयतः अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के बड़वानी और शाजापुर में विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर मध्य प्रदेश के विकास की अनदेखी करने वाली पार्टी बताते हुए राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चल रही विकास यात्रा में सारा भारतवर्ष एकजुट है। मध्य प्रदेश में पिछली बार से भी अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है।

श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने दो विकल्प है - एक ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसने विगत 15 वर्षों में श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को 'बीमारू' से 'विकसित' राज्य बनाया, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश को 'बीमारू' राज्य बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है जिसका न तो कोई नेता है, न नीति, न नीयत और न ही कोई सिद्धांत। उन्होंने कहा कि एक ओर जनता के बीच से निकले हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व है तो दूसरी ओर राजा, महाराजा और उद्योगपतियों की कांग्रेस पार्टी जिसके 10 वर्षों के सोनिया-मनमोहन सरकार में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के घपले-घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि हम श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस बताये कि राज्य में उसका नेता कौन है?

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार के समय मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि महज साढ़े सात लाख हेक्टेयर थी, जबकि शिवराज सरकार ने इसे बढ़ा कर 40 लाख हेक्टेयर करने का काम किया है। अगले पांच सालों में हमारा लक्ष्य प्रदेश की 80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार किसानों से कृषि ऋण पर 18% का ब्याज वसूलती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्याज को घटाते-घटाते ख़त्म कर दिया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार जहां किसानों को कृषि के लिए केवल 1,300 करोड़ रुपये का ऋण देती थी, जबकि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इसे बढ़ा कर 13,588 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार के समय केवल 214 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन होता था, जबकि शिवराज सरकार के समय आज 545 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य पर तेज गति से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य का निर्धारण कर किसानों को सशक्त बनाने का काम किया है। आज बोनस के साथ धान के फसल की खरीद की जा रही है, राज्य में 80 लाख से अधिक कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड दिया गया और नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की कालाबाजारी ख़त्म की गयी।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास झूठ बोलने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। सभी कांग्रेसी नेताओं को 15 साल बाद अचानक मध्य प्रदेश का विकास याद आने लगा है। श्रीमान बंटाधार की सरकार थी तब गांवों में सड़कें नहीं थी, आज हर गांव सड़क से जुड़ गया है। 15 साल पहले गांवों में बिजली नहीं थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पेयजल - हर क्षेत्र में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास के आयाम ही बदल दिए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी हर दिन झूठ का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं और ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि श्री नरेन्द्र मोदी जी ने साढ़े चार सालों में क्या किया? अरे राहुल गांधी जी, केंद्र में आपकी चार-चार पीढ़ियों ने शासन किया, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आपने क्या किया, पहले इसका हिसाब तो प्रदेश की जनता को दीजिये! उन्होंने कहा कि केंद्र में 55 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, राज्य में कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन न तो आदिवासी भाई-बहनों के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ किया और न ही प्रदेश के विकास के लिए। उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सोनिया-मनमोहन की सरकार रही, लेकिन इस दौरान कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या किया - इसका हिसाब राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज को देना चाहिए। लेकिन ये हिसाब देंगे नहीं क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कुछ किया ही नहीं है, बस जनता को गुमराह करते रहेंगे।

राहुल गांधी के भाषणों पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी अपने पूरे भाषण में कभी इस पर बात नहीं करते कि उनका राज्य के विकास का एजंडा क्या है या उन्होंने राज्य के विकास के लिए क्या किया, बस मोदी नाम की माला जपते रहते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का! दरअसल राहुल गांधी को 'मोदीफोबिया' हो गया है। राहुल गांधी को सीख देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मध्य प्रदेश में आप सपने देखने बंद कर दो, यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यह श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और श्री प्यारेलाल खंडेलवाल की भूमि है, यहां कांग्रेस की दाल कभी भी गलनेवाली नहीं है। ■

# शिवराजजी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश 'बीमारू' से 'विकसित' बना है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 नवंबर को मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उमरिया और चुरहट में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की।

कांग्रेस में परिवारवाद और वंशवाद की विष-बेल पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रदेश का सेनापति तय नहीं होता, सेनापति केवल राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है। वह भी केवल एक परिवार में जन्म लेने भर से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेहरू-गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस पर एक परिवार के सिवा किसी और का अधिकार कभी नहीं हो सकता।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कांग्रेस को एक गैर नेहरू-गांधी परिवार के सदस्य को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की चुनौती देने वाले बयान से कांग्रेस पार्टी के कई रागदरबारियों को तीखी मिर्ची लगी है, जो अपनी 'वफादारी' साबित करने के लिए सीमारेखा से बाहर हो रहे हैं। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के सटीक निशाने ने एक दुखती रग पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का बयान बिलकुल सही है क्योंकि इतिहास गवाह है कि 'एक परिवार' की पूजा के कारण कांग्रेस पार्टी में कई बड़े नेताओं के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया गया, बल्कि साजिश कर उन्हें दरकिनार भी किया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक राजा, एक महाराजा और एक उद्योगपति की तिकड़ी मध्य प्रदेश का भला कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने तो महलों के बाहर की जिंदगी कभी देखी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तो गरीबी को जिया है, इसे महसूस किया है और श्री शिवराज सिंह चौहान गरीब किसान परिवार में जन्म लेकर यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के केंद्र में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, युवा एवं महिलायें ही हैं। हमारा लक्ष्य 'अंत्योदय' के सिद्धांत पर चल कर 'सबका साथ, सबका विकास' करना है। उन्होंने कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश 'बीमारु' से 'विकसित' बना है। अगले पांच सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुआई में श्री शिवराज जी प्रदेश को 'समृद्ध' बनाने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का बस एक ही काम रह गया है - झूठ बोलना, बार-बार झूठ बोलना और सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमसे चार सालों के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस से 55 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग के दौरान कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को विकास के लिए महज लगभग 1,34,190 करोड़ रुपये की राशि दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में राज्य के लिए 3,44,126 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मुद्रा बैंक योजना में लगभग 32,000 करोड़, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 984 करोड़, अमृत मिशन के लिए 2593 कोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 427 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 22 करोड़, इंदौर मेट्रो के लिए 7000 करोड़, भोपाल मेट्रो के लिए 7000 कोर्ड, इंटीग्रेटेड को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए 1794 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये, कुल 57,000 करोड़ रुपये अलग से मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। ■

# 'कांग्रेस को एक परिवार के सिवा किसी और की चिंता नहीं है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 19 नवंबर को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, बैतूल और खातेगांव (देवास) में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया राज्य की जनता से विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि राज्य की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जारी विकास यात्रा में भागीदार बनते हुए प्रदेश में भाजपा की श्री शिवराज सरकार बनाने का निर्णय पहले से ले लिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता नफरत की साजिश के बीज बो कर राजनीति करने वाली कांग्रेस को कभी भी माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कदम-कदम पर मध्य प्रदेश के साथ अन्याय ही अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा मोदी जी और शिवराज जी जैसे जनसेवकों की जोड़ी ही कर सकती है। कांग्रेस कभी जनता का भला नहीं कर सकती, क्योंकि वो नेहरू-गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसे एक परिवार के सिवा किसी और की चिंता नहीं है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को आज भी यह याद है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह अपने कुशासन से प्रदेश को एक 'बीमारू' राज्य बनाया था जिसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निरंतर अपने अथक प्रयासों से एक 'विकसित' प्रदेश बनाया है। राज्य की जनता कभी कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता के समक्ष दो ही विकल्प हैं - एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य के गांव-गांव, घर-घर का विकास करने वाली श्री शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी सरकार, वहीं दूसरी तरफ देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी जिसका न कोई नेता है, न नीति और न ही कोई

सिद्धांत।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इतनी बार नाम लेते हैं कि लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि राहुल गांधी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का। वास्तव में, राहुल गांधी समेत पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को 'मोदीफोबिया' हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी का एक ही एजेंडा है - मोदी हटाओ, जबकि हमारा एजेंडा देश से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा और अंधेरे को हटाना है। उन्होंने जनता से प्रश्न करते हुए कहा कि आपको लोक-कल्याणकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहिए या फिर मध्य प्रदेश को समस्याओं के गर्त में डुबोने वाली कांग्रेस सरकार? (सभा में उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में शिवराज सरकार को लाने का संकल्प व्यक्त किया।)

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में अपनी जीत का दिवास्वप्न दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले साढ़े चार सालों में कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई है कि उसे दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनाव और उसके बाद देश में संपन्न हुए लगभग सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की पराजय निश्चित है।

**मध्यप्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि राज्य की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जारी विकास यात्रा में भागीदार बनते हुए प्रदेश में भाजपा की श्री शिवराज सरकार बनाने का निर्णय पहले से ले लिया है। देश की जनता नफरत की साजिश के बीज बो कर राजनीति करने वाली कांग्रेस को कभी भी माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कदम-कदम पर मध्य प्रदेश के साथ अन्याय ही अन्याय किया है।**

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बजट किसी भी सरकार के विकास का परिचायक होता है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के समय मध्य प्रदेश का वार्षिक बजट महज 21,700 करोड़ रुपये का था, जबकि शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार में यह बढ़कर लगभग 1,85,900 करोड़ रुपये पहुंचा है। प्रति व्यक्ति आय 14 हजार रुपये से पांच गुना से भी अधिक बढ़कर 72 हजार करोड़ रुपया हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बंटाधार सरकार के शासन में गांवों में बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश में केवल 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था जबकि आज मध्य प्रदेश 17,700 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है। दिग्विजय सिंह की सरकार के समय मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि महज साढ़े सात लाख हेक्टेयर थी, जबकि शिवराज सरकार ने इसे बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर करने का काम किया है। अगले पांच सालों में हमारा लक्ष्य प्रदेश की 80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना है। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार किसानों से कृषि ऋण पर 18% का ब्याज वसूलती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्याज को घटाते-घटाते ख़त्म कर दिया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कभी भी समर्थन मूल्य पर जनता से फसल की खरीद नहीं की, जबकि आज शिवराज सरकार समर्थन मूल्य पर बोनस के साथ धान और गेहूं खरीद रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय राज्य की विकास दर - 4% थी जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विगत 15 सालों में राज्य की औसत विकास दर 10.8% रही है। दिग्विजय सिंह की सरकार के समय मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन महज 214 लाख मीट्रिक टन था, जबकि शिवराज सिंह सरकार के समय राज्य का कृषि उत्पादन 545 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। अगले पांच साल में शिवराज सरकार राज्य के किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार के बीच तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह सरकार में प्राथमिकशालाएं 56 हजार से बढ़कर 83 हजार, माध्यमिकशालाएं 18 हजार से बढ़कर 30 हजार, इंजीनियरिंग कॉलेज 104 से बढ़कर 306 और मेडिकल कॉलेज 5 से बढ़कर 18 हुई हैं।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि आप मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के विकास के आंकड़े और हमारी सरकार के विकास के आंकड़ें लेकर आयें, हमारा कोई भी कार्यकर्ता राज्य के किसी भी शहर में आप से बहस के लिए तैयार है, लेकिन आप झूठे वादे कर जनता को गुमराह न करें। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग के दौरान कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को विकास के लिए महज लगभग 1,34,190 करोड़ रुपये की राशि दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में राज्य के लिए 3,44,126 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मुद्रा बैंक योजना में लगभग 32,000 करोड़, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 984 करोड़, अमृत मिशन के लिए 2593 कोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 427 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 22 करोड़, इंदौर मेट्रो के लिए 7000 करोड़, भोपाल मेट्रो के लिए 7000 कोर्ड, इंटीग्रेटेड को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए 1794 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये, कुल 57,000 करोड़ रुपये अलग से मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। ■

## कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

## प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

# आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

# सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

| सदस्यता | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एक वर्ष | ₹350/- | ☐ | आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी) | ₹3000/- | ☐ |
| | तीन वर्ष | ₹1000/- | ☐ | आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी) | ₹5000/- | ☐ |

**(भुगतान विवरण)**

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

**अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें**

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

**कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका**

सिंगापुर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सिंगापुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भारतीय समुदाय के लोग

सिंगापुर आगमन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मिलते सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सीन लूंग

अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

रीवा (मध्य प्रदेश) में एक विशाल रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

**प्रेषण तिथि:** (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
**डाकघर:** लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20